साप्ताहिक
शांति मिशन
नई दिल्ली

वर्ष-28 अंक- 30 25 - 31 जुलाई 2021 पृष्ठ 12

अन्दर पढ़िए

इंटरनेट की टूटती साँसें पृष्ठ-6

शराब की बिक्री से किसका भला होगा? पृष्ठ-7

एनडीए की दूसरी पारी में मोदी सरकार का विस्तार

क्या है राजनीतिक संदेश

स्वास्थ्य एवं सहकारिता मंत्रालय की ही तरह अन्य मंत्रालयों का ज़िम्मा जिन मंत्रियों को दिया गया है उसके पीछे बहुत सोची-समझी रणनीति है।

गुजरात में 1998 तक सरकारी संस्थानों, बैंकों में कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। सिर्फ एक सहकारी बैंक पर भाजपा काबिज़ थी। अमित शाह ने सहकारी संस्थानों से कांग्रेस को बेदख़ल करने की योजना तैयार की। धीरे-धीरे कांग्रेस गुजरात के सहकारी संस्थानों से पूरी तरह ग़ायब हो गई। अब जब नरेन्द्र मोदी ने नया सहकारिता मंत्रालय बनाया तो उसके मंत्री के तौर पर अमित शाह को नियुक्त किया। दरअसल यह दृष्टांत ही तय कर देता है? पारंपरिक तरीके से राजनीति को देखने पर शायद ही समझ में आए कि गृह मंत्रालय के साथ सहकारिता मंत्रालय एक ही व्यक्ति को भला कैसे दिया जा सकता है, लेकिन इसी सोच के तहत मनसुख मांडविया नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का ज़िम्मा वह किस प्रकार ठीक से संभाल पाएंगे, इसे समझने के लिए उस प्रसंग को याद करें जब नितिन गडकरी को स्पष्ट करना पड़ा था कि वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने को लेकर मैंने कुछ सुझाव दिए थे, पर मुझे जानकारी नहीं थी कि मांडविया पहले ही बता चुके थे कि यह सब हो चुका है।

स्वास्थ्य और सहकारिता मंत्रालय की ही तरह दूसरे मंत्रालयों का ज़िम्मा जिन मंत्रियों को दिया गया है, उसके पीछे बहुत सोची समझी रणनीति है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि मंत्रीमंडल से हटाए गए मंत्रियों रविशंकर प्रसाद, रमेश पोखरियाल निशंक, प्रकाश जावड़ेकर और डॉ॰ हर्षवर्धन को हटाने के पीछे यह एक सूत्र है कि वे मोदी सरकार के राष्ट्रीय विमर्श को स्थापित करने में कामयाब नहीं रहे। मोदी सरकार के बारे में एक बात पक्के तौर पर कही जाती है कि वह फीडबैक पर काम करने वाली सरकार है और विशेषकर जनता क्या चाहती है, यह उसके लिए बहुत महत्व रखता है। किसी भी सरकार के वैचारिक विमर्श को स्थापित करने में सूचना प्रसारण मंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन जावडेकर उस भूमिका से न्याय नहीं कर पाए और अब अनुराग सिंह ठाकुर को यह ज़िम्मा सौंपा गया है। शिक्षा मंत्री के तौर पर निशंक का पूरा समय सिर्फ विवादों और टालमटोली में ही बीतता रहा। देश के आधे से अधिक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपति नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करके राष्ट्रीय विमर्श को आगे बढ़ाने की दिशा में भी शिक्षा मंत्रालय कुछ विशेष नहीं कर सका। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सबसे पैनी दृष्टि भी इसी मंत्रालय के कामकाज पर रहती है, फिर भी शैक्षणिक संस्थानों में विरोधी विचार का कब्ज़ा बना रहा। इसे संघ ने बहुत गंभीरता से लिया। इन हालात को बदलने की ज़िम्मेदारी अब धर्मेंद्र प्रधान को सौंपी गई है। प्रधान लम्बे समय तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् से जुड़े रहे हैं। वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय में प्रधान की विरासत को अब हरदीप सिंह पुरी आगे बढ़ाएंगे। पुरी के पास आवास और शहरी विकास का प्रभार पहले से ही है। पंजाब चुनाव से पहले सिख चेहरे के तौर पर और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर कांग्रेस के दुष्प्रचार को ध्वस्त करने के लिहाज़ से विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी पुरी की विशेष उपयोगिता हो सकती है।

43 नए मंत्रियों में असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर से एक-एक प्रतिनिधि जोड़ गए हैं, जो पूर्वोत्तर के प्रति मोदी की दृष्टि को प्रमाणित करता है। चीन से सटे अरुणाचल प्रदेश के किरण रिजीजू को केन्द्रीय क़ानून मंत्री की कुर्सी देना दिखाता है कि प्रधानमंत्री के लिए रिजीजू रणनीतिक तौर पर कितने महत्वपूर्ण हो गए हैं। पूर्व नौकरशाह अश्विनी वैष्णव को रेलवे, कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय देने के पीछे बहुत स्पष्ट वजह है। वह वाजपेयी सरकार में उपसचिव रहे हैं। दो पूर्व नौकरशाह और 24 पेशेवर मोदी सरकार में बदलाव का हिस्सा बने हैं। 43 नए मंत्रियों में 61 प्रतिशत मंत्री अन्य पिछड़े, अनुसूचित जाति और जनजाति से हैं। 27 ओबीसी, 12 एससी और आठ एसटी मंत्रियों को मोदी ने शामिल किया तो कई चैनलों ने 'अबकी बार ओबीसी सरकार' तक लिख दिया। एक समय मुख्य रूप से ब्राह्मण-बनियों की पार्टी मानी जाने

बाक़ी पेज 11 पर

सरकारी जासूसी पर संसद में हंगामा

वेदप्रताप वैदिक

हमारी संसद के दोनों सदन पहले दिन ही स्थगित हो गए। जो नए मंत्री बने थे, प्रधानमंत्री उनका परिचय भी नहीं करवा सके। विपक्षी सदस्यों ने सरकारी जासूसी का मामला ज़ोरों से उठा दिया हैं उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह देश के लगभग 300 नेताओं, पत्रकारों और जजों आदि की जासूसी कर रही है। इन लोगों में 02 केन्द्रीय मंत्री, 03 विरोधी नेता, 40 पत्रकार और कई अन्य व्यवसायों के लोग भी शामिल हैं।

यह जासूसी इस्राईल की एक प्रसिद्ध कंपनी के सॉफ्टवेयर 'पेगासस' के माध्यम से होती है। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके सरकार देश के महत्वपूर्ण लोगों के ई-मेल, व्हाट्ऐप्प और संवाद सुनती है। यह रहस्योद्घाटन सिर्फ भारत के बारे में ही नहीं हुआ है, इस तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल 40 देशों की संस्थाएं या सरकारें कर रही हैं। लगभग 50,000 लोगों की जासूसी की जा रही है। इस सॉफ्टवेयर को बनाने वाली कंपनी एन.एस.ओ. ने दावा किया है कि वह अपना यह माल सिर्फ संप्रभु सरकारों को ही बेचती है ताकि वे आतंकवादी, हिंसक, अपराधी और अराजक तत्वों पर निगरानी रख सकें।

इस कंपनी के रहस्यों का भंडाफोड़ कर दिया फ्रांस की कंपनी 'फारबिडन स्टोरी' तथा 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' ने। इन दोनों कंपनियों ने उक्त भंडाफोड़ की ख़बरें कई देशों के प्रमुख अख़बारों में छपवा दी है। भारत में जैसे ही यह ख़बर सामने आई, तहलका-सा मच गया। अभी तक उन 300 लोगों के नाम प्रकट नहीं हुए हैं लेकिन कुछ पत्रकारों के नामों की चर्चा है। विरोधी नेताओं ने सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस घटना से यह सिद्ध हो गया है कि मोदी-राज में भारत 'पुलिस स्टेट' बन गया है। सरकार अपने मंत्रियों तक की जासूसी करती है और पत्रकारों की जासूसी करके वह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को खोखला कर रही है। सरकार ने इन आरोपों का खण्डन किया है। उसने कहा है कि पिछले वर्ष भी 'पेगासस' को लेकर ऐसे आरोप लगे थे, जो निराधार सिद्ध हुए थे। नए सूचना मंत्री ने संसद को बताया कि किसी भी व्यक्ति की गुप्त निगरानी करने के बारे में कानून कायदे बने हुए हैं। सरकार उनका सदा पालन करती है। 'पेगासस' संबंधी आरोप निराधार है।

यहां असली प्रश्न यह है कि इस सरकारी जासूसी को सिद्ध करने के लिए क्या विपक्ष ठोस सबूत जुटा पाएगा? यदि ठोस सबूत मिल गए और सरकार विरोधी लोगों के नाम उनमें पाए गए तो सरकार को लेने के देने पड़ सकते हैं। इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी और लोकतंत्र की हत्या की संज्ञा दी जाएगी। यूं तो पुरोन राजा-महाराजा और दुनिया की सभी सरकारें अपना जासूसी तंत्र मज़बूती से चलाती हैं, लेकिन यदि उसकी पोल खुल जाए तो वह जासूसी तंत्र ही क्या हुआ। जहां तक पत्रकारों और नेताओं का प्रश्न है, उनका जीवन तो खुली किताब की तरह होना चाहिए। उन्हें जासूसी से क्यों डरना चाहिए? वे जो कहें और जो करें वह खम ठोक कर करना चाहिए। ❑❑

अफ़ग़ानिस्तान

इस विदाई पर कोई रोए या हँसे

अफ़ग़ानिस्तान से अमेरिका जा रहा है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि एक बार फिर से जा रहा है। पिछले कई सालों से यह तो स्पष्ट हो गया था कि उसका जाना तय है, पर वापसी का समय किसी को मालूम नहीं था, यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपतियों को भी नहीं। बुश से लेकर ट्रम्प तक कोई नीति नियामक नहीं जानता था कि वह कैसे और कब उस दलदल से निकलेगा, जिसमें सोवियत रूस को फंसाने के चक्कर में उसने खुद को आकंठ धंसा लिया है? जो बाइडेन ने तो अपने को समय की तेज़ धार में आंख मूंदकर छोड़ दिया था। अब देखना यह है कि जिस तेज़ बहाव ने अमेरिका को अफगानिस्तान से बाहर निकाल फेंका है, वह उसे अपने पैरों पर मज़बूती से ज़मीन पर खड़ा होने का मौक़ा कब तक देगा.?

अफग़ानिस्तान अपनी भू-राजनीतिक के कारण सैकड़ों सालों से महाशक्तियों की दिलचस्पी का क्षेत्र रहा है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश और रूसी साम्राज्य के हित यहां टकराए, तो 20वीं शताब्दी ने अमेरिकी कूटनीति के जाल में सोवियत रूस को इसकी पहाड़ियों पर फंसते और अपमानित होते देखा है। यह विडंबना हे कि आज जब खरबों डॉलर और सैकड़ों जानों का नुकसान उठाकर अमेरिका सिर झुकाव रणभूमि से बाहर जा रहा है, तब उसके धुर विरोधी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें तालियां बजानी चाहिए या वे चिंता के सिर झुका लें।

भारत की परेशानी समझ में आ सकती हैं पिछले दो दशकों में उने जो बड़ा निवेश अफग़ानिस्तान में किया था, वह तालिबान के आते ही बेकार हो जाएगा। अमेरिकी सैनिकों की विदाई के 10 दिन के भीतर उसे कंधार का वाणिज्य दूतावास बंद करना पड़ा है। दावा तो 80 प्रतिशत भूभाग का है, पर इसमें कोई शक नहीं कि आधी से अधिक धरती पर तालिबान कब्ज़ा कर चुके हैं। रूस, चीन ईरान, जो पारंपरिक रूप से अमेरिका विरोधी है, उनके माथे पर झुर्रियां दिख रही हैं। कबीलों में बंटे अफग़ानी समाज में कोई भी इस आशंका से प्रसन्न नहीं है कि सारी ताक़त इस्लाम का अतिवादी भाष्य करने वाले सुन्नी पश्तूनों के हाथ में आ जाएगी। अफग़ान धरती में छिपे खनिज और मध्य एशिया से व्यापार की कुंजी कोई खोना नहीं चाहता। कह सभी रहे थे, पर अंदर से चाहता कोई नहीं था कि बिना सारे मसले हर किए अमेरिका चला जाए।

जिसे सबसे अधिक खुश होना चाहिए था, वह पाकिस्तान भी कम परेशान नहीं हैं यह दीवार पर लिखी इबारत की तरह स्पष्ट है कि चंद महीनों में इतिहास अपने को दोहराएगा और काबुल पर फिर तालिबान का कब्ज़ा हो जाएगा। सब कुछ पुरानी पटकथा की तरह ही हो रहा है। एक के बाद एक इलाके आसानी से सरकारी नियंत्रण से निकलते जा रहे हैं, सरकारी

भारत की परेशानी समझ में आ सकती हैं पिछले दो दशकों में उने जो बड़ा निवेश अफग़ानिस्तान में किया था, वह तालिबान के आते ही बेकार हो जाएगा। अमेरिकी सैनिकों की विदाई के 10 दिन के भीतर उसे कंधार का वाणिज्य दूतावास बंद करना पड़ा है। दावा तो 80 प्रतिशत भूभाग का है, पर इसमें कोई शक नहीं कि आधी से अधिक धरती पर तालिबान कब्ज़ा कर चुके हैं।

सैनिकों की बड़ी संख्या या तो बिना लड़े समर्पण कर दे रही है, या फिर भागकर पड़ोसी देशों में शरण ले रही है। अपनी निर्मिति तालिबान की विजय पर तो पाकिस्तान को खुश होना चाहिए, फिर उसकी परेशानी का सबब क्या हो सकता है?

कुछ दिनों पहले इस्लामाबाद सिक्युरिटी डायलॉग में बोलते हुए पाक सेनाध्यक्ष जनरल क़मर जावेद बजवा ने पहली बार कहा कि काबुल में युद्धरत सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार बने। यह पहली बार हो रहा था कि पाकिस्तान तालिबान के अलावा दूसरे गुटों को भी सत्ता में भागीदारी देने की बात कर रहा था। यह भी पहली बार ही है कि सेना इस तरह का रुख़ अपना रही है। पिछली बार जब तालिबान कंधार या काबुल को घेर रहे थे, तब पाक सेना की टुकड़ियां उनके साथ थीं। इस बार उन्हें सिर्फ संसाधनों की मदद मिली। लगता है, इमरान ख़ान के नेतृत्व वाला नागरिक प्रशासन दिग्भ्रमित है। नीतियों के स्तर पर मतभेद के बावजूद सैनिक और असैनिक, दोनों नेतृत्व यह तो समझ ही चुके हैं कि एक बार अफग़ानिस्तान में फारिग़ होने के बाद तालिबान का ध्यान पाकिस्तान पर जाएगा। पिछली बार की तरह ही वे अपने देश में अपनी समझ का इस्लामी निज़ाम नाफिज़ करने के बाद पड़ोस में भी शरिया लागू कराने आ जाएंगे। पिछला अनुभव बताता है कि हज़ारों नागरिकों के क़त्ल और अरबों रुपयों के संसाधनों की बर्बादी के बाद ही देश उस मध्ययुगीन बर्बर जीवन पद्धति से बच सका, जिसमें तालिबान उसे धकेल देना चाहते थे। वही ख़तरा फिर मंडरा रहा है, शायद इसीलिए बार-बार अमेरिका की हार की भविष्यवाणी करने वाले पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रहा कि वे उसकी विदाई के मौक़े पर हंसे या रोएं?

क़ाबुल में तालिबान सरकार एक से अधिक अर्थों में भारत को प्रभावित करेगी। अफग़ानिस्तान के अंदर पिछले दो दशकों का निवेश इस अर्थ में तो प्रासंगिक रहेगा कि उसने आम अफग़ानियों के मन में भारत की सकारात्मक छवि बनाई है, पर अब वहां किसी बड़ी वाणिज्यिक परियोजना की परिकल्पना निकट भविष्य में संभव नहीं लगती। यहां तक कि चाहबहार बंदरगाह की सफलता भी संदिग्ध हो गई है। इससे ज़्यादा चिंताजनक वह आशंका है, जिसके अंतर्गत अफग़ानिस्तान में ख़ाली होते ही जेहादियों के कश्मीर का रुख़ करने का अनुमान है। पाकिस्तान इसीलिए उन्हें पालता-पोसता रहा है। मुझे याद है 1990 का दशक, जब एशिया व अफ्रीका के तमाम मुल्कों के जेहादी घाटी में दिखने लगे थे। वे बोस्निया, चेचन्या और अफगानिस्तान के गृह युद्धों से तपकर निकले लड़ाके थे, जिन्होंने भारतीय सुरक्षा बलों के लिए

बाक़ी पेज 11 पर

मेट्रो चलाने में कमाई से ढाई गुना ज़्यादा हो रहा है ख़र्च : मंगू सिंह

कोविड ने दिल्ली मैट्रो की आर्थिक स्थिति पर जमकर चोट की है। अनलॉक होने के बाद मेट्रो सेवाएं चल रही हैं, लेकिन उसकी क्षमता के मुक़ाबले छह से दस प्रतिशत यात्री ही सफर कर पा रहे हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि दिल्ली मेट्रो की आमदनी में भारी कमी आई है। कोविड का मेट्रो परियोजनाओं पर असर, ख़र्चे कम करने के लिए मेट्रो क्या कुछ दूसरे काम हाथ लेने में लेने की सोच रही है? क्या मेट्रो ट्रेनों का निजीकरण हो रहा है? ऐसे ही सवालों के जवाब जानने के लिए पेश है मेट्रो के एमडी मंगू सिंह ने बातचीत के प्रमुख अंश।

प्रश्नः- दिल्ली मेट्रो फेज-4 की इस वक्त क्या स्थिति है? कोविड का क्या असर पड़ा है?

उत्तरः- अब तक मेट्रो फेज-4 का औसतन 14 प्रतिशत काम हुआ है। कुछ जगह पर अभी पेड़ों को काटने के लिए अनुमति की प्रक्रिया चल रही है। कोविड की वजह से कामकाज तो प्रभावित हुआ ही है दरअसल, जब काम बंद होता है तो ऐसा नहीं है कि कामकाज उतने दिन ही प्रभावित होता है बल्कि इसका लम्बे समय तक असर चलता है। मगर, इतना ज़रूर है कि कुछ लाइनों पर आधुनिक मशीनें आ गई हैं, जिससे काम की रफ्तार बनाए रखने की कोशिश होगी।

प्रश्नः- क्या फेज-4 की डेडलाइन बढ़ानी होगी और इसकी लागत पर भी असर पड़ेगा?

उत्तरः- यह ज़रूरी नहीं है कि डेडलाइन बढ़ानी ही पड़े। अभी देखना होगा कि कोविड का आने वाले दिनों में कितना असर होता है। अब तक काम में जो देरी हुई है, उसे क्या हम कवर कर पाऐं। इसे अभी देखना होगा। इसी तरह के लागत के बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाज़ी होगी।

प्रश्नः- कोविड के बाद अब मेट्रो की वित्तीय हालत कैसी है?

उत्तरः- इस समय दिल्ली मेट्रो की वित्तीय स्थिति भारी दबाव में है। फिलहाल दिल्ली मेट्रो की आमदनी एक रूपये है और उसे ढाई रूपये ख़र्च करने पड़ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जो फिक्स खर्च है, उन्हें तो कम करना मुश्किल है। इसमें कर्मचारियों का वेतन, मेट्रो के सेफ्टी से जुड़े रख/रखाव के काम, पॉवल बिल का फिक्स चार्ज आदि। दूसरी ओर मेट्रो की आमदनी बेहद कम हो गई है। प्रॉपटी डिवेलपमेंट से जो आमदनी होती थी, वह भी प्रभावित हुई है। मेट्रो को अपने लोन की किस्ते तो चुकानी ही पड़ रही है।

प्रश्नः- आमदनी पर कितना असर पड़ा है?

उत्तरः- 2019-20 के वित्तीय वर्ष में दिल्ली मेट्रो को यात्री किराए आदि से 3897 करोड़ रुपये की आमदनी थी और खर्च के मुक़ाबले 895.88 करोड़ रुपये हमारे पास सरप्लस थे। इस वर्ष मार्च में खत्म हुए वित्तीय वर्ष में हमारी आमदनी कम होकर 758 करोड़ रुपये रह गई। इसी तरह से पिछले वर्ष जो 895 करोड़ सरप्लस थे, वे मार्च में खत्म हुए साल में निगेटिव 1784 करोड़ रुपये हो गए। यानि 1784 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। एक तरह से हमारी आमदनी में ही एक वर्ष में 3100 करोड़ रुपये की कमी हुई। अप्रैल से शुरू हुए वित्तीय वर्ष में भी मैट्रो अपनी क्षमता का छह से दस प्रतिशत यात्री ही ले जा रही है।

प्रश्नः- क्या मेट्रो अपने रिजर्व रक़म का इस्तेमाल कर रही है। कितने वर्ष तक इस रिजर्व से काम चल सकता है? क्या इस बारे में केन्द्र सरकार से बात की गई है?

उत्तरः- अभी आमदनी के मुक़ाबले खर्च दो से ढाई गुणा है। ज़ाहिर है रिजर्व से ही मेट्रो अपना ख़र्च चला रही है। लेकिन लम्बे समय तक नहीं चल सकता। हमने रख रखाव के कुछ ऐसे काम टाल दिए हैं जिनका सेफ्टी से कोई संबंध नहीं है। उनमें रंग-रोग़न आदि के काम शामिल हैं। आर्थिक मदद का प्रश्न है, तो हमने सिर्फ केन्द्र ही नहीं, दिल्ली, यूपी और हरियाणा सरकारों से कहा है। इन राज्यों में भी मेट्रो ट्रेनें चलती हैं। मगर, अभी कुछ हुआ नहीं है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे कुछ सुधार हो।

प्रश्नः- मेट्रो क्या प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कुछ काम करके पैसे का इंतज़ाम करने पर विचार कर रही है?

उत्तरः- प्राइवेट सेक्टर की भी यही हालत है। प्राइवेट वाले खुद उल्टा राहत मांग रहे हैं प्रॉपर्टी डिवेलपमेंट के तहत जो दुकानें दी हैं वे लोग भी छोड़कर जा रहे थे। उनसे बात की ताकि दुकानें ख़ाली न पड़ी रहें। मोलभाव करके उन्हें रोकने की कोशिश की है।

प्रश्नः- दिल्ली मेट्रो तो कंसल्टेंसी करके भी पैसा कमाती है, वहां क्या स्थिति है?

उत्तरः- कंसल्टेंसी से जो पैसा कमाया, वही अब मेट्रो के काम आ रहा है। जयपुर मेट्रो का ऑपरेशन का काम हो या फिर दूसरी मेट्रो निर्माण में सलाहकार के रूप में किया गया काम। उससे मेट्रो को जो आमदनी हुई, वह हमारे काम आ रही है।

प्रश्नः- प्राइवेट मेट्रो ट्रेनें चलाने की योजना कहां तक पहुंची? उससे क्या मेट्रो के ख़र्चों में कमी आएगी?

उत्तरः- प्राइवेट मेट्रो ट्रेन नहीं चला रहे बल्कि आउटसोर्स ट्रेन ड्राइवर नियुक्त कर रहे हैं। जैसे हमने मेट्रो स्टेशनों पर टिकट बांटने वाला स्टाफ, सफाई आदि का काम आउसोस किया है उसी तरह से अब ट्रेन चलाने वाले ऑपरेटर हम आउटसोर्स कर रहे हैं। इसके तहत काट्रैक्टर हमें ट्रेने चलाने के लिए कर्मचारी मुहैया करा रहा है। इसके तहत ट्रेने चलाने वाले 153 ड्राईवरों को मेट्रो ने ट्रेनिंग दी हैं 70 ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। ये ड्राइवर येलो लाइन पर ट्रेने चलाएंगे। इसी तरह चरणबद्ध तरीके से दूसरी लाइनों के लिए भी ड्राइवर काट्रैक्टर के ज़रिए ही लिए जाएंगे।

प्रश्नः- ऑपरेशन प्राइवेट लोगों को देना सेफ्टी के लिहाज़ से ख़तरनाक नहीं होगा?

उत्तरः- ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्रेने चलाने के लिए हम खुद ड्राईवर को प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद जब उसे प्रमाण पत्र मिलेगा, तभी वह ट्रेन चलाएगा। ये सभी ड्राइवर मेट्रो के स्टाफ की निगरानी में काम करेंगे। वैसे भी हमारे पास आधुनिक मैट्रो ट्रेन हैं, जिनमें ड्राइवर से अधिक सिस्टम काम करता है। ❑❑

संपादकीय

शांति मिशन

यह अदालती सिस्टम की हत्या है

इस वर्ष अप्रेल के अंत माह में उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस एनवी रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और एएस बोपन्ना की तीन सदस्यीय पीठ ने पत्रकार सिद्दिक कप्पन को दिल्ली के अस्पताल में बेहतर इलाज का आदेश दिया। आदेश में न्यायमूर्तियों ने जो टिप्पणी की, वह एक नज़ीर है। अदालत ने कहा, 'हमारा मानना है कि एक विचाराधीर क़ैदी को भी बिना किसी शर्त के जीने का मौलिक अधिकार, सबसे कीमती है।' हाथरस में दलित बेटी के साथ हुए सामूहिक बलात्कार की घटना को कवर करने जाते केरल के पत्रकार कप्पन को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पिछले साल 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के हालात देखकर देश की सभी सरकारों-अदालतों को कुछ दिशा निर्देशों के साथ आदेश दिया था कि ऐसे क़ैदियों को अंतरिम ज़मानत या पैरोल पर जेलों से रिहा करें। भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी 84 वर्ष के फादर स्टैन स्वामी उन दिशा निर्देशों की परिधि में आते थे, मगर उनकी ज़मानत की अर्ज़ी ख़ारिज हुई।

जब दोबारा गंभीर बीमारी की हालत में दाख़िल की गई, तो तुरंत सुनवाई नहीं हुई। उनके जीने का हक़ छीना गया। अस्पताल में तब दाख़िल कराया गया, जब हालत गंभीर हो गई। पार्किन्सन बीमारी से पीड़ित फादर स्टैन स्वामी को पानी पीने के लिए एक स्ट्रॉ भी नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए भी याचिका में आग्रह करना पड़ा, तब एनआईए ने कहा कि, वे अगली तारीख़ पर जवाब देगी। अगली तारीख़ से पहले ही स्वामी ने दम तोड़ दिया। फादर स्टैन स्वामी बगैर अपराध के 9 माह जेल में प्रताड़ित होते रहे और शूली पर चढ़ गये। हमें फादर स्टैन स्वामी से चर्चा और उनका काम देखने का अवसर मिला था। वह मानवता की सेवा करने वाले एक साधारण से दिखते व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था, कि दबे-कुचले और यातना का शिकार आदिवासी उन्हें भगवान मानते थे।

वह ऐसे व्यक्ति थे, जिनसे किसी को ख़तरा हो ही नहीं सकता। दु:ख तो यह होता है कि एनआईए ने इस बुज़ुर्ग को हुकमत के लिए ख़तरा बता दिया। जो कभी भीमा कोरेगांव गया ही नहीं। उनके कम्प्यूटर में वहां की घटनाओं का ब्यौरा होने को आधार बाकर उन्हें षड्यंत्र का मुलज़िम बना दिया गया था। यह भी सत्य है कि छोटी छोटी बातों में डरने वाली सत्ता, सदैव भय में रहती है। जांच एजेंसियां इसका फायदा उठाकर ऐसे ही आरोपों में न जाने कितने निर्दोष जनों और जनता की आवाज़ बनने वालों को जेलों में डाल देती हैं।

फरीदाबाद से दो वर्ष पहले प्रोफेसर सुधा भारद्वाज को भी गिरफ्तार किया गया था। उनके ख़िलाफ़ भी कोई सबूत नहीं है मगर वह जेल में हैं। अदालत सच देखकर भी मौन साधे है। मानवाधिकार की आवाज़ बननने वाली सुधा को भी सरकार ने अपने लिए ख़तरा मान लिया। वह दबे कुचलों की लड़ाई लड़ती थीं। उन्हें जेल में किताब पढ़ने के लिए भी अदालत में याचिका दाख़िल करनी पड़ी। इस मामले में ढाई वर्ष पहले गिरफ्तार रोना विल्सन ने हाईकोर्ट में याचिका दाख़िल कर बताया था कि उनके लैपटॉप को हैक करके नकली सबूत प्लांट किये गये हैं, उन्होंने इसको साबित करने के लिए डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट भी अदालत में पेश की। मैसाचुसेट्स स्थित डिजिटल फोरेंसिक फर्म, आर्सेनल कंसल्टिंग से रोना के लैपटॉप की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी का परीक्षण किया था। उसने रिपोर्ट में कहा है कि, रोना की गिरफ्तारी के करीब 22 माह पहले उनके कम्प्यूटर में एक मैलवेयर भेज कर उसे हैक किया गया था। कई अटेंप्ट करके उनके कम्प्यूटर में 10 दस्तावेज़ 'प्लांट' किए गये थे। इन्हीं से कनेक्शन जोड़कर फादर स्टेन स्वामी और सुधा भारद्वाज को भी अपराधी बनाया गया था।

अदालती सिस्टम से उम्मीद की जाती है कि वह उसके समक्ष प्रस्तुत किये गये सबूतों और तथ्यों का परीक्षण कर शीघ्रता से न्याय करेगा, मगर इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। अदालतों ने सदैव देरी की और तथ्यों की अनदेखी की। गिरफ्तार किये गये इन मानवाधिकार सेवकों को कोरोना महामारी के दौर में भी मरने के लिए छोड़ दिया गया। प्रश्न तब उठता है जब हम देखते हैं कि किसी को ज़मानत देने के लिए आधी रात में अदालतें लग जाती हैं, तो दूसरी ओर वास्तविक पीड़ितों की वाजिब दलील भी नहीं सुनी जाती।

साफ है कि पैसा और सत्ताबल आपके पास है, तो न्याय व्यवस्था आपकी मुट्ठी में है, अन्यथा आप इंसाफ़ के लिए लड़ते अपनी ज़िन्दगी ख़त्म कर देंगे। पिछले वर्ष उच्चतम न्यायालय के जस्टिस दीपक गुप्ता ने अपने संबोधन में अदालती सिस्टम पर प्रश्न उठाए थे। उन्होंने कहा था कि देश का क़ानून और न्याय तंत्र चंद अमीरों और ताक़तवर लोगों की मुट्ठी में क़ैद है। हम पहले भी देख चुके हैं कि हमारी दोषपूर्ण न्यायिक व्यवस्था के कारण हज़ारों निर्दोष लोगों की ज़िन्दगी जेल में ही कट जाती है। इसका एक उदाहरण ललितपुर का विष्णु तिवारी है जिसने 20 वर्ष जेल में उस जुर्म के लिए कांटे, जो उसने किया ही नहीं था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के शोधार्थी गुलज़ार अहमद वानी को साबरमती एक्सप्रेस में धमाके के लिए 16 साल लखनऊ जेल में काटने पड़े। जब उसकी ज़िन्दगी बर्बाद हो गई तब अदालत ने उसे निर्दोष माना। उसे फंसाने वालों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। कर्नाटक में भाजपा मुख्यालय के सामने हुए बम विस्फोट में 27 आरोपी आठ साल से यूएपीए में बंद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी बग़ैर किसी ट्रायल के क़ैद हैं। इनमें से किसी पर भी अब तक आरोप भी मय नहीं हुए हैं। फरीदाबाद के खोड़ा गांव के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया मगर पास ही खड़ी बड़ी इमारतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट कोई टिप्पणी नहीं की। न्याय व्यवस्था दोषपूर्ण न रहे, इसको लेकर 2014 में भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था। उन्होंने मिनिमम गवर्नमेंट, मैग्जिमम गवर्नेंस का वादा किया था। पिछले सात साल में यह वादा तो पूरा नहीं हुआ बल्कि उसके उलट हो रहा है। हमें याद आता है कि 1789 में हुई फ्रांस की क्रांति से पहले वहां कोई व्यवस्थित न्यायपालिका नहीं थी। राजा स्वेच्छा से क़ानून बनाते और लागू करते थे। उनमें एकरूपता का अभाव था क्रांति के बाद सुधार शुरू हुआ।

नेपोलियन बोनापार्ट के राज में क़ानूनों में एकरूपता लाई गई। ब्रिटेन में भी 1873 से पहले न्यायिक व्यवस्था दोषपूर्ण थी। रॉयल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर उसमें सुधार किया गया। आमजन के हित में क़ानूनी व्यवस्था का निर्माण किया गया। ब्रिटिश हुकूमत में हमारे देश में भी न्यायिक व्यवस्था में सुधार शुरू हुआ मगर हम पर शासन करने के उद्देश्य से। देश की आज़ादी के बाद काफी कुछ सुधार हुआ। तात्कालीन सरकारें लोकतंत्र और लोकहित पर अधिक ध्यान देने लगी। क़ानूनों का दुरुपयोग करने वालों को सज़ा दिये जाने की व्यवस्था की गई।

इससे हालात सुधरे मगर कालांतर में सत्ता धनबल पर कब्ज़ा जमाये बैठे लोगों और दबाव समूहों के हाथों में यह व्यवस्था आ गई है। फादर स्टैन स्वामी की मौत, उसी का नतीजा हैं यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार शाखा ने भारत सरकार को चेताया है। हमें अगर देश को खूबसूरत और खुशहाल बनाना है, तो सबसे पहले नागरिकों के हितों पर ध्यान देना होगा। उनको क़ानून के शासन में बांधना होगा। त्वरित न्याय की व्यवस्था को सुनिश्चित करना होगा। अगर ऐसा नहीं होगा, तो हम विश्व में शर्मिन्दा होते रहेंगे। हमें सबके लिए समान क़ानून और न्याय व्यवस्था बनानी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश अराजकता और ताक़तवर लोगों की मुट्ठी में आ जाएगा। ❑❑

तारीख़े इस्लाम

ख़ुतबाते सीरते तैयिबा

मुफ़्ती मुहम्मद सलमान मंसूरपुरी क़िस्त- 82

अब आप अंदाज़ा लगाइये कि एक मुअ़ज़्ज़ज़ तरीन ख़ातून और पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम की चहेती ज़ौजा मुतहहरा पर जब ऐसा इलज़ाम लगा होगा, तो पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम को कितनी अज़ीयत हुई होगी, हज़रत आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि अल्लाहु अ़न्हा बिल्कुल भोली भाली ख़ातून थीं, उन्हें कुछ पता नहीं कि लोग उनके बारे में क्या क्या कह रहे हैं? और मदीना मुनव्वरा जब क़ाफ़िला पहुंचा, तो यह बात सब के कानों में पहुंच कर पूरे मदीने में फ़ैल गई, नबी-ए-अकरम अ़लैहिस्सलाम ने हज़रत आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि अल्लाहु अन्हा से कोई बात नहीं फ़रमाई, एक महीना ऐसे ही गुज़र गया, लेकिन हज़रत का अंदाज़ यह था कि ख़ैरियत वग़ैरह तो मालूम करते लेकिन पहले जैसी बशाशत(ख़ुशी) नहीं थी, हज़रत आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि अल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि बात क्या है? एक दिन ऐसा हुआ कि हज़रत आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि अल्लाहु अ़न्हा क़ज़ाये हाजत के लिए जंगल जा रही थीं (उस ज़माने में घरों में बैतुल ख़ला तो थे नहीं) उनको ले जाने के लिए उम्मे मिस्तह नामी एक औ़रत मुतअ़"यन थीं, साथ जाते जाते ऐसा हुआ कि उन्होंने परदे के लिए जो चादर ओढ़ रखी थी, अचानक उस में उनका पैर फिसल कर गिरने के क़रीब हो गई, तो उम्मे मिस्तह ने यह जुमला कहा: (मिस्तह बरबाद हो) मिस्तह उनके साहब ज़ादे थे, यह अब्दुल्लाह बिन उबई के कहने में आकर हज़रत आ़इशा रज़ि अल्लाहु अ़न्हा के ख़िलाफ़ मुहिम चलाये हुए थे, हज़रत आ़इशा रज़ि अल्लाहु अ़न्हा ने फ़रमाया कि अल्लाह की बंदी! मिस्तह तो नेक आदमी हैं, तुम उन को बद दुआ क्यों दे रही हो? उम्मे मिस्तह ने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं, उस ने क्या क्या अफ़वाहें फ़ैला रखी हैं, और कहा कि वह तुम्हारे बारे में ऐसा वैसा कहता है। (अल-बिदाया वन्निहाया जि. 4 स. 548, बुख़ारी शरीफ़, 2/594)

हज़रत आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि अल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि उस वक़्त मुझे मालूम हुआ कि पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम का यह रव"या मेरे साथ क्यों है? मेरे पैरों के नीचे से तो ज़मीन निकल गई, और मैंने नबी-ए-अकरम अ़लैहिस्सलाम से इजाज़त ली कि मैं अपने वालिदैन से मिलने के लिए जाना चाहती हूँ, हज़रत ने इजाज़त दे दी, फ़रमाती हैं कि मेरा हाल यह था कि रोते रोते मेरी आँखों के आँसू ख़ुश्क हो चुके थे, क्योंकि मेरा अल्लाह जानता है कि मेरे वहम व गुमान में भी कभी ग़लत बात नहीं आई, और पैग़म्बर की ज़ौजा मुतहहरा के दिल में ऐसी बात का आना ना मुम्किन है, अल्लाह तआ़ला नबी को भी बा इ़ज़्ज़त रखते हैं और नबी के घर वालों को भी बा इ़ज़्ज़त रखते हैं, उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, और उन मुनाफ़िक़ीन ख़बीसों ने यह वबाल खड़ा कर दिया था। (बुख़ारी शरीफ़, 2/595)

एक दिन का वाक़िआ़ है कि नबी-ए-अकरम अ़लैहिस्सलाम हज़रत आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि अल्लाहु अ़न्हा से मिलने के लिए उनके घर तशरीफ़ लाए, और हज़रत आ़इशा रज़ि अल्लाहु अ़न्हा को बुलाया, और फ़रमाया कि आ़इशा! देखो इनसान बहरहाल इनसान है, अगर कोई ग़लती हो गई हो, तो इक़रार करने में आ़फ़ियत है, तो हज़रत आ़इशा फ़रमाती हैं कि मेरी आँखों से आँसू ख़ुश्क हो चुके थे, मैंने अपने वालिद हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि अल्लाहु अ़न्हु से कहा कि आप जवाब दीजिये, उन्होंने कहा कि मेरी हिम्मत नहीं, वालिदा उम्मे रोमान से कहा कि आप जवाब दीजिये, उन्होंने भी कहा कि मेरी हिम्मत नहीं। तो हज़रत आ़इशा रज़ि अल्लाहु अ़न्हा ने ख़ुद जवाब दिया, और फ़रमाया कि "हज़रत मैं इस मोड़ पर हूँ कि अगर यह कहूँ कि मैं इस से बरी हूँ यानी सच बोलूँ तो आप यक़ीन नहीं करेंगे, और अगर झूठ बोलूं तो हो सकता है कि आप के दिल में यक़ीन आ जाए, इस लिए मैं तो यह कहती हूँ कि :

यानी मैं सब्र करती हूँ और अल्लाह ही से मदद चाहती हूँ"

मैं ज्योतिषी तो नहीं, लेकिन भाजपा-जजपा सरकार टूटेगी, मध्यावधि चुनाव होंगे : चौटाला

जेबीटी भर्ती घोटाले में 10 वर्ष की सज़ा पूरी कर लौटे इनेलो सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला अब फिर सक्रिय हो रहे हैं। 86 वर्ष की आयु में इस पारी का आगाज़ वह किसान आंदोलन स्थलों के दौरों के साथ कर रहे हैं। साथ वह यह भविष्यवाणी भी कर रहे हैं कि भाजपा/जजपा सरकार टूटेगी और मध्यावधि चुनाव होंगे। साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को चुनाव में हराने की चुनौती भी दे रहे हैं। पेश है चौटाला जी से हुई एक बातचीत के प्रमुख अंश :-

प्रश्नः- ओपी चौटाला जेल नहीं जाते तो प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर क्या होती?

उत्तरः- मैं बाहर रहता तो 2014 में इनेलो की सरकार बननी थी। आज ये लोग स्वार्थ का गठबंधन करके सरकार चला रहे हैं। लोग परेशान हैं और आंदोलन कर रहे हैं। मैं रहता तो लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान न होना पड़ता। इस सरकार में लोगों की सुनवाई नही होती। युवाओं के रोज़गार छीन लिए। भाजपा के पास सबसे ज़्यादा चंदा आ रहा है। यह ज़बरदस्ती लूटा जा रहा है। जो सरकार वादे पूरे न कर पाए उसे इस्तीफा देना चाहिए।

प्रश्नः- आपके लौटने से राजनीतिक हलचल है। क्या प्रदेश में मध्यावधि चुनाव होंगे?

उत्तरः- लोगों को 2024 का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मैं ज्योतिषि तो नहीं हूं पर प्रदेश के हालात देखकर कह सकता हूं कि यह सरकार टूट जाएगी। सरकार से जुड़े लोग इसे छोड़ देंगे। सरकार जब अल्पमत में रहेगी तो निश्चित तौर पर मध्यावधि चुनाव के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।

प्रश्नः- आप सरकार की निंदा कर रहे हैं लेकिन आपके पोते दुष्यंत भी तो उसका हिस्सा हैं?

उत्तरः- मैं ही नहीं, बल्कि आम लोग यह महसूस करते हैं कि इन लड़कों के गलत निर्णय के कारण गलत लोगों के हाथ में सत्ता चली गई है।

प्रश्नः- आप भी तो भाजपा के साथ गठबंधन करते रहे हैं। फिर जेजेपी कैसे ग़लत है.?

उत्तरः- वो समय अलग था। जेजेपी/भाजपा का स्वार्थ का गठबंधन है। आज इनेलो का ग्राफ इतनी ऊपर चला गया है कि में किसी से गठबंधन की ज़रूरत नहीं।

प्रश्नः- अजय और आप जेल में साथ थे। क्या पार्टी परिवार में फूट रोकने की कोशिश नहीं की.?

उत्तरः- कुछ स्वार्थी लोगों ने सत्ता के लिए यह सब किया। वो मौज लूटने गए थे, पर आज उन्हें मार पड़ रही है। आपको क्या लगता है? मैंने प्रयास नहीं किए? कुछ लोगों ने स्वार्थ में पार्टी तोड़ी। ऐसे लोग किसी के नहीं है।

प्रश्नः- इनेलो 01 सीट पर सिमट गई। कहां खामियां रहीं? क्या पुराने नेताओं को फिर साथ जोड़ेंगे?

उत्तरः- ख़ामियां कहीं नहीं थी। स्वार्थी लोग सत्ता पक्ष में चले गए। वे वहां अपमानित हो रहे हैं। नीचे भीड़ में भी कई बार कुर्सी के हत्थे पर बैठना पड़ता हैं। अशोक अरोड़ा 18 वर्ष हमारी पार्टी के अध्यक्ष रहे। आज हुड्डा के बेटे दीपेन्द्र का ड्राइवर बनने को मजबूर है। इससे ज़्यादा अपमान क्या होगा? पार्टी छोड़ने वाले ही नहीं, बल्कि दूसरे दलों के लोग भी इनेलो में आ रहे हैं, जो अपनी ग़लती मानकर लौटना चाहता है आ सकता है।

प्रश्नः- आप 86 वर्ष के हैं। अब आगे चुनाव लड़ेंगे या सिर्फ मार्ग दर्शक की भूमिका में रहेंगे?

उत्तरः- मैं संगठन का आदमी हूं। संगठन कहेगा तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो लड़वाऊंगा। मुझे गांव गांव जाना है। मौसम ठीक होने पर सभी से मिलकर हालचाल जानूंगा। कोरोना के हालात ठीक हुए तो बड़ी रैली करके प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार को खाड़ने की मुहिम खड़ी करूंगा।

प्रश्नः- माना जाता है कि सीएम के चेहरे पर इनेलो टूटी। अगले चुनाव में पार्टी का चेहरा कौन होगा? चुनाव किसके ख़िलाफ़ लड़ेंगे..?

उत्तरः- पार्टी का बहुमत आने पर प्रतिनिधि जो निर्णय लेंगे, वो ही मुझे और सभी को मान्य होगा। मैं खट्टर या हुड्डा किसी के ख़िलाफ भी चुनाव जीत सकता हूं। लेकिन मुझे क्या करना है, यह मैं नहीं संगठन तय करेगा।

प्रश्नः- आप किसान आंदोलन में जा रहे हैं। पर किसान नेता कहते हैं कि राजनीतिक लोगों को मंच पर जगह नहीं देंगे?

उत्तरः- मैं राजनीति करने नहीं, बल्कि किसानों का धन्यवाद करने जा रहा हूं। वो बधाई के पात्र हैं। किसान आंदोलन में 36 जात के लोग शामिल हैं देश में सभी सरकारें जात-पात का ज़हर फैलाती आई हे। यह पहला अवसर है, जब जातपात का भेद ख़त्म हो गया। सरकार इसमें भी जातपात का ज़हर घोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएगी।

प्रश्नः- क्या आप समाधान की कोई पहल करेंगे..?

उत्तरः- सरकार चाहे भाजपा की रही हो या कांग्रेस की, सबने किसानों का शोषण किया है। सरकार की मंशा किसान को उसके ही खेत में मज़दूर बनाने की है। किसान मजबूर होकर आंदोलन कर रहे हैं। जिन्हें सड़कों पर हज़ारों लोग दिख नहीं रहे, मेरे पत्र से उन पर क्या असर होगा। बात करके समाधान निकालना सरकार की ज़िम्मेदारी है।

प्रश्नः- केन्द्र में नरेन्द्र मोदी का क्या विकल्प देखते हैं? क्या तीसरे मोर्चे की मुहिम से जुड़ेंगे?

उत्तरः- विकल्प तलाशे नहीं जाते, खुद पैदा होते हैं। कांग्रेस सरकार का जब पतन हुआ था, तब भी विकल्प खुद सामने आया था। आज भी तैयार होगा। स्व. देवीलाल ने जिस तरह तीसरे मोर्चे में भूमिका निभाई थी, ज़रूरी पड़ी तो मैं भी देशभर में सबको एकजुट करने के लिए सभी से मिलूंगा।

प्रश्नः- वृद्धावस्था में 10 वर्ष की जेल कैसे काटे? इस दौरान आपमें क्या बदलाव आया

उत्तरः- कोई बदलाव नहीं आया। यही सोचता था कि कैसे बाहर जाकर फिर से लोगों का भला कर सकूं। सत्तारूढ़ लोगों ने दुष्प्रचार किया था कि चौटाला जेल में ही मर जाएगा और इनका दल बिखर जाएगा। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैंने सज़ा पूरी की और कार्यकर्ताओं ने संगठन को मज़बूत किया।

प्रश्नः-भविष्य में जेजेपी के साथ गठबंधन की कोई संभावना देखते हैं?

उत्तरः- जेजेपी का अगले चुनाव तक वजूद ही नहीं रहेगा। अजय और दुष्यंत ने देवीलाल को दादा न मानकर गौतम को दादा माना था। लेकिन उनके नकली दादा ने तो उन्हे छोड़ दिया। इनके साथ गए लोग इन्हें छोड़कर चले जाएंगे। मुझे चोट लगने के बाद वे हालचाल पूछने भी नहीं आए। ❑❑

कांग्रेस के भले की लिए सिद्धू और अमरेंद्र पुराने विवाद भुलाएं

कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की पंजाब इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर आलाकमान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका सफर अभी शुरू हुआ है और वह राज्य में पार्टी संगठन को मज़बूत करने के लिए और अधिक काम करेंगे। सिद्धू और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के बीच कई माह की कड़वाहट और गुटबाज़ी के दौर के बाद सिद्धू को कांग्रेस की पंजाब इकाई की कमान सौंपी गई है।

कांग्रेस आलाकमान द्वारा गठित मल्लिकार्जुन समिति पंजाब के 100 से अधिक नेताओं से बातचीत तथा अमरेन्द्र सिंह और नवजोत सिद्धू सहित पंजाब के कांग्रेस नेताओं की दिल्ली में राहुल और प्रियंका गांधी के साथ मुलाक़ातों के बावजूद इसे दूर करने में विफल रही। मुख्यमंत्री अमरेन्द्र सिंह ने सोनिया गांधी से 06 जुलाई को भेंट की परंतु कोई नतीजा न निकला।

17 जुलाई को हरीश रावत के साथ चंडीगढ़ में भेंट के बाद अमरेन्द्र सिंह ने कहा कि उन्हें सोनिया गांधी का हर फैसला मंज़ूर होगा परंतु इस बैठक में अमरेन्द्र ने रावत के सामने कुछ ऐसे सवाल उठाए जिनका वह जवाब नहीं दे पाए। अमरेन्द्र ने यह भी कहा कि जब तक सिद्धू अपने टवीटों के बारे में सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते तब तक उनसे भेंट नहीं होगी।

एक ओर कैप्टन अमरेन्द्र सिंह 18 जुलाई को सिद्धू की माफी पर अड़े थे तो दूसरी ओर इसी दिन अंततः रात 9 बजे के लगभग कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी किए जाने की घोषणा कर दी गई।

जो भी हो अमरेन्द्र और नवजोत सिद्धू को चाहिए कि दोनों से ही कुछ छोटी छोटी गलतियां अवश्य हुई होंगी। अमरेन्द्र सिंह 1984 में ऑप्रेशन ब्ल्यू स्टार के विरोध में संसद सदस्यता से इस्तीफा देकर अकाली दल में शामिल हो गए थे और अंत तक कांग्रेसी ही रहे।

अन्त में सारी बीती बातें भुलाकर दोनों को अपनी कटुता भुलाकर पार्टी हित में काम में जुट जाना चाहिए। दोनों के दिलों का मिलन ज़रूरी है इसी में उनका, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस वर्करों का भला है, वर्ना इस आपसी द्वेष का फायदा उचके ने के लिए तो भाजपा है ही। ❑❑

मेरठ में मस्जिद की दीवार गिरने से 2 की मौत, 9 लोग बुरी तरह घायल, नमाज के फौरन बाद हुआ

उत्तर प्रदेश के मेरठ में लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के अहमदनगर में आज दोपहर एक मस्जिद की दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। यह हादसा आज जुमे की नमाज़ के फौरन बाद हुआ। जिस समय यह हादसा हुआ, उस समय मस्जिद में 40-50 लोग मौजूद थे, जो बारिश की वजह से मस्जिद में रुक गए थे। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के भीड़भाड़ वाले इलाके में स्थित मस्जिद का नाम मोहम्मदिया मस्जिद है। यह हादसा नमाज़ पढ़ने के दौरान नहीं हुआ, बल्कि जब लोग जुमे की नमाज़ पढ़कर लोग घर लौट रहे थे तभी तेज बारिश आने के चलते कुछ लोग मस्जिद में ही रुक गए और उस दौरान मस्जिद की एक निर्माणाधीन दीवार गिर गई, जिसमें दर्जनों लोग दब गए। इस दौरान चीख-पुकार मच गई और लोगों की भीड़ इकठा हो गई। मरने वालों का नाम अफ्फान और बबलू बताया जा रहा है, जबकि घायलों में फुरकान, इरशाद, नूर मोहम्मद, नदीम और शाहिद बताए जा रहे हैं। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय विधायक रीक अंसारी और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसपी सिटी विनीत भटनागर और सिटी मजिस्ट्रेट सतेंद्र कुमार लसह ने काफी तत्परता दिखाते हुए हादसे में दबे घायलों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। एसपी सिटी, सिटी मजिस्ट्रेट समेत पुलिस अधिकारी मौके पर हैं और बचाव कार्य चल रहा है। अहमदनगर की गली नम्बर 9 में स्थित जिस मस्जिद में यह हादसा हुआ, उसकी हालात बिल्कुल भी खराब नहह्ल थी। दीवार हाल के दिनों में बनकर तैयार हुग्र थी, मगर स्थानीय लोगों की मानें तो जर्जर बिल्कुल नह्ी थी। स्थानीय निवासी अदनान अंसारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मस्जिद का छज्जा टूटने से यह हादसा हुआ है। यह बारिश की वजह से हो सकता है, क्योंकि दीवारें गीली हो चुकी हैं। राहत की बात यह है कि कोरोना गाइडलाइंस के चलते मस्जिद में बहुत कम लोग नमाज़ पढ़ रहे थे। सामान्य दिनों में यह हादसा बहुत बड़ा हो सकता था।

चित्रकूट में संघ का चिंतन

उत्तर प्रदेश के चुनाव कैसे जीते जाएं इस पर गहन चिंतन के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी अधिकारियों और प्रचारकों का एक सम्मेलन चित्रकूट में हुआ। ऐसे शिविर में हुई कोई भी वार्ता या लिए गए निर्णय इतने गोपनीय रखे जाते हैं कि वे कभी बाहर नहीं आते। मीडिया में जो ख़बरें छपती हैं वे केवल अनुमान पर आधारित होती हैं, क्योंकि संघ के प्रचारक कभी असली बात बाहर किसी से सांझा नहीं करते। इसलिए अटकलें लगाने के बजाय हम अपनी सामान्य बुद्धि से इस महत्वपूर्ण शिविर के उद्देश्य, वार्ता के विषय और रणनीति पर अपने विचार तो समाज के सामने रख ही सकते हैं।

जहां तक उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा के चुनाव की बात है तो जिस तरह की अफरा तफरी संघ और भाजपा में मची है उससे यह तो स्पष्ट है कि योगी सरकार की फिर से जीत को लेकर गहरी आशंका व्यक्त की जा रही है, जो निर्मूल नहीं है। संघ और भाजपा के गोपनीय सर्वेक्षणों में योगी सरकार क लोकप्रियता वैसी नहीं सामने आई जैसा सैकड़ों करोड़ों के विज्ञापन दिखाकर छवि बनाने की कोशिश की गई और की जा रही है।

ये ठीक वैसा ही है, जैसा 2004 के लोकसभा चुनाव में वाजपेयी जी के चुनाव प्रचार को तत्कालीन भाजपा नेता प्रमोद महाजन ने 'इंडिया शाइनिंग' का नारा देकर खूब ढिंढोरा पीटा था। विपक्ष तब भी बिखरा हुआ था। वाजपेयी जी की लोकप्रियता के सामने सोनिया गांधी को बहुत हल्के में लिया जा रहा था। सुषमा स्वराज और प्रमोद महाजन ने तो उन्हें विदेशी बताकर काफी पीछे धकेलने का प्रयास किया। पर परिणाम भाजपा और संघ की आशा के प्रतिकूल आएं ऐसा ही दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल आदि राज्यों के विधान सभा चुनावों में भी हुआ। जहां संघ और भाजपा ने हर हथकंडे अपनाए, हज़ारों करोड़ रुपया खर्च किया, पर मतदाताओं ने उसे नकार दिया।

अगर योगी जी के शासन की बा करें तो याद करना होगा कि मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने सबसे पहले क़दम क्या उठाए, रोमियो स्क्वाड, क़त्लखाने और मांस की दुकानों पर छापे, लव जेहाद का नारा और दंगों में मुसलमानों को आरोपित करके उन पर पुलिस का सख़्त डंडा या उनकी सम्पत्ति कुर्क करना जैसे कुछ चर्चित कदम उठाकर योगी ने उत्तर प्रदेश के कट्टर हिन्दुओं का दिल जीत लिया। दशकों बाद कोई ऐसा मुख्यमंत्री आया है जो हिन्दुत्व के मुद्दे को पूरे दम-खम से लागू करेगा पर यह मोह जल्दी ही भंग हो गया। योगी की इस कार्यशैली के प्रशंसक अब पहले की तुलना में काफी कम हो गए हें।

इसका मुख्य कारण है कि योगी राज में बेरोज़गारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। महंगाई तो सारे देश में ही आसमान छू रही है तो उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। इसके साथ ही नोटबंदी और जी.एस.टी. के कारण तमाम उद्योग धंधे और व्यवसाय ठप्प हो गए हैं, जिसके कारण उत्तर प्रदेश की बहुसंख्यक जनता आर्थिक रूप से बदहाल हुई है।

रही-सही मार कोविड काल में, विशेषकर दूसरी लहर में, स्वास्थ्य सेवाओं की बुरी तरह विफलता ने पूरी कर डाली। कोई घर ऐसा न होगा जिसका परिचित या रिश्तेदार इस अव्यवस्था के कारण मौत की भेंट न चढ़ा हो। बड़ी तादाद में लाशों को गंगा में बहाया जाना या दफ़नाया जाना एक ऐसा हृदयविदारक अनुभव था, जो हिन्दू शासन काल में हिन्दुओं की आत्मा तक में सिहरन पैदा कर गया। क्योंकि 1000 वर्ष के मुसलमानों के शासनकाल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब आर्थिक तंगी या लकड़ी की अनुपलब्धता के कारण हिन्दुओं को अपने प्रियजनों के शवों का दफ़नाना पड़ा हो। इस भयानक त्रासदी से हिन्दू मन पर जो चोट लगी है उसे भूलने में सदियों बीत जाएंगी।

योगी सरकार के कुछ अधिकारी उन्हें गुमराज कर हज़ारों करोड़ रुपया हिन्दु के नाम पर नाटक नौटंकियों पर ख़र्च करवाते रहे जिससे योगी सरकार को क्षणिक वाह-वाही तो मिल गई, लेकिन इसका आम मतदाता को कोई भी लाभ नहीं मिला। बहुत बड़ी रक़म इन नाच गानों और आडंबर पर बर्बाद हो गई। प्रयागराज के अर्द्ध-कुंभ को पूर्ण कुम्भ बता कर हज़ारों करोड़ रुपया बर्बाद करना या वृंदावन की 'कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक' को भी कोविड काल में पूर्ण कुंभ की तरह महिला मंडित करना शेख चिल्ली वाले काम थे। मथुरा जिले में तो कोरोना की दूसरी लहर वृंदावन के इसी अनियंत्रित आयोजन के बाद ही बुरी तरह आई। जिसके कारण हर गांव ने मौत का मंज़र देखा। कोविड काल में संघ की कोई भूमिका नज़र नहीं आई। न तो दवा और इंजेक्शनों की काला बाज़ारी रोकने में न अस्पतालों में बैड के लिए बदहवास दौड़ते परिवारों की मदद करने में और न ही ग़रीब परिवारों को दाह संस्कार के लिए लकड़ी उपलब्ध कराने के लिए।

मथुरा, अयोध्या और काशी के विकास के नाम पर दिल खोलकर ध न लुटाया गया। पर दृष्टि, अनुभव, ज्ञान व धर्म के प्रति संवेदनशीलता के अभाव में हवाई विशेषज्ञों की सलाह पर यह धन भ्रष्टाचार और बर्बादी का कारण बना। जिसका कोई प्रशंसनीय बदलाव इन धर्म नगरियों में नहीं दिखाई पड़ रहा है। आधुनिकीकरण के नाम पर प्राचीन धरोहरों को जिस बेदर्दी से नष्ट किया गया उससे काशीवासियों और दुनिया भर में काशी की अनूठी गलियों के प्रशंसकों को ऐसा हृदयाघात लगा है क्योंकि वे इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। सदियों की सांस्कृतिक विरासत को बुल्डोजरों ने निर्ममता से धूलधूसरित कर दिया।

योगी सरकार ने गौ सेवा और गौ रक्षा के अभियान को भी खुले हाथ से सैकड़ों करोड़ रुपया दिया जो एक सराहनीय क़दम था। पर दुर्भाग्य से यहां भी संघ और भाजपा के बड़े लोगों ने मिलकर गौशालाओं पर कब्जे करने का और गौ सेवा के धन को उर्र-फुर्र करने का ऐसा निदंनीय कृत्य किा है जिससे गौ माता इन्हें कभी क्षमा नहीं करेंगी। इस आरोप को सिद्ध करने के लिए तमाम प्रमाण उपलब्ध हैं।

इन सब कमियों को समय-समय पर जब पत्रकारों या जागरुक नागरिकों ने उजाकर किया या प्रश्न पूछे तो उन पर दर्जनों एफ.आई.आर. दर्ज करवा कर लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा निदंनीय कार्य हुआ जैसा उत्तर प्रदेश की जनता ने पहले कभी नहीं देखा था। इसलिए केवल यह मान कर कि विपक्ष बिखरा है, वैतरणी पार नहीं होगी। क्या विकल्प बनेगा या नहीं बनेगा यह तो समय बताएगा।

पर आश्चर्य की बात यह है कि जिस घबराहट में संघ आज सक्रिय हुआ है अगर समय रहते उसने चारों ओर से उठ रही आवाज़ों को सुना होता तो स्थिति इतनी न बिगड़ती। पर यह भी हिन्दुओं का दुर्भाग्य है कि जब-जब संघ वालों को सत्ता मिलती है, उनका अहंकार आसमान को छूने गता है। देश और धर्म की सेवा के नाम पर फिर जो नौटंकी चलती है उसका पटाक्षेप प्रभु करते हैं और हर मतदाता उसमें अपनी भूमिका निभाता है। ❑❑

रोज़गार .....

'सेवा' और 'कमाई' साथ-साथ

आज पूरी दुनिया में हेल्थ केयर वर्कर्स सरकार और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। डॉक्टर्स के बाद नर्स एक ऐसा पद है जो सेवा के ज़रिए लोगों को संतुष्टि भी रहा है, जो मानवता की सेवा के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप में भी सेवाभाव, सहनशीलता और समर्पण जैसे गुणों के साथ रोगियो-दुखियों की सेवा करने का जुनून है तो नर्सिंग आपके लिए बेहतरीन कैरियर है।

ऐसे करें शुरुआत

नर्स (परिचारिका/परिचारक) बनने से इच्छुक लोग (महिला व पुरुष) सहायक नर्स मिडवाइफ/हेल्थ वर्कर (ए.एन.एम.) कोर्स से शुरू कर सकते हैं। इस डिप्लोमा कोर्स की अवधि डेढ़ वर्ष है और न्यूनतम योग्यता 10वीं पास हैं। इसके आप जनरल नर्स मिडवाइफरी (जी.एन.एस.) कोर्स भी कर सकते हैं, जो साढ़े तीन साल का होता है। इसके लिए न्यूनतम योग्यता 40 प्रतिशत अंकों के साथ भौतिक, रासायनिक एवं जीव विज्ञान में 12वीं उत्तीर्ण होना है।

ए.एन.एम. व जी.एन.एम. के अलावा देशभर में फैले हुए विभिन्न नर्सिंग स्कूलों-कॉलेजों से नर्सिंग में स्नातक भी की जा सकती है इसके लिए न्यूनतम योग्यता 45 प्रतिशत अंकों के साथ अंग्रेजी, भौतिक, रासायनिक एवं जीव विज्ञान में 12वीं उत्तीर्ण रखी गई है। इसके लिए आपकी आयु कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए।

बी.एस.सी. नर्सिंग (बेसिक के पश्चात्) पाठ्यक्रम के लिए आप दो वर्ष के रेगुलर कोर्स या त्रिवर्षीय दूरस्थ शिक्षा वाले पाठयक्रम में से किसी एक को चुन सकते हैं। रेगुलर कोर्स के लिए जहां न्यूनतम योग्यता 10+2+जी.एन.एम. है, वही दूरस्थ शिक्षा से यह कोर्स करने के लिए न्यूनतम योग्यता 10+2+जी.एन.एम.+दो वर्ष का अनुभव है। बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग कोर्स ही आधुनिक माना जाता है।

भारतीय रक्षा सेवाओं द्वारा संचालित बी.एस.सी. (नर्सिंग) कोर्स के लिए 17 से 24 वर्ष की महिलाओं का चयन किया जाता है। प्रार्थी को एक लिखित परीक्षा भी पास करनी होती है। चयनित लोगों को रक्षा सेवाओं के लिए 05 वर्ष का अनुबंध करना होता है।

शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप अपने राज्य की नर्सिंग काउंसिलिंग में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीयन आपको जॉब प्राप्त करने में मदद करता हैं

नर्सिंग के बेसिक कोर्स के अलावा आप पोस्ट बेसिक स्पैशियलिटी (एक वर्षीय डिप्लोमा) कोर्स करके इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता भी हासिल कर सकते हैं - कार्डियक एवं डिजास्टर नर्सिंग, क्रिटिकल - केयर नर्सिंग, एमरजेंसी एवं डिजास्टर नर्सिंग नवजात की परिचर्या (नियो - नेटल नर्सिंग), मस्तिष्क संबंधी रोगों में परिचर्या (न्यूरो नर्सिंग), नर्सिंग शिक्षा एवं प्रशासन, कर्क (कैंसर) रोग संबंधी नर्सिंग (आन्कोलॉजी नर्सिंग), ऑपरेशन रूम नर्सिंग, विकलांग चिकित्सा नर्सिंग, मिड वाइफरी प्रेक्टिशनर, मनोरोग परिचर्या (साइकेट्रिक नर्सिंग)

कितना होगा ख़र्च

नर्सिंग की पढाई का ख़र्च संस्थान पर निर्भर करता है। सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज, निजी संस्थानों की अपेक्षा कम दर पर शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। निजी संस्थान बी.एस.सी., नर्सिंग कोर्स के लिए 40,000 से 1,80,000 तक वार्षिक फीस वसूलते हैं। जी.एन.एम. कोर्स के लिए यहां फीस 45,000 से, 1,40,000 के बीच होती है।

नौकरी के अपार अवसर

सरकारी अथवा निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, अनाथाश्रम, वृद्धामद्व अयोग्य निवास, विभिन्न अन्य उद्योगों एवं रक्षा सेवाओं में ट्रेंड नर्सों के लिए नौकरी के अपार अवसर हैं। इंडियन रैड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल्स और अन्य नर्सिंग संस्थानों में भी कई अवसर हैं। यहां तक कि ए.एन.एम. कोर्स के बाद ही इन्हें सारे देश में फैले हुए प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवक के रूप में नौकरी मिल जाती है।

वेतनमान

इस क्षेत्र में शुरुआती तौर पर आपको 07 से 17 हजार रुपए तक मासिक वेतन मिल सकता है। मिड लेवल पदों पर नर्सें 18 से 37 हजार प्राप्त कर लेती हैं। अधिक अनुभवी नर्सों को 48 से 72 हजार रुपए तक भी मासिक वेतन के रूप में मिल सकते हैं। अमरीका, कनाडा, इंग्लैंड व मध्य पूर्व के देशों में रोज़गार पाने वाली नर्सों को इससे भी अधिक वेतन मिलता है।

विदेशों में भी जॉब के अवसर

विदेशों में उच्च शिक्षित नर्सों की बहुत मांग है। भारत कई देशों में नर्सों की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश बन चुका है। अच्छे पैसे व बेहतर रहन-सहन की चाहत में अनुभवी भारतीय नर्सें विदेशों का रुख़ करने लगी हैं। देश में नर्सों की संख्या में कमी की एक बड़ी वजह यह भी है। ❑❑

इस्लामी दुनिया

बांग्लादेश में सभी को नि:शुल्क लगाए जाएंगे कोरोना टीके

ढाका : बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख़ हसीना ने कहा कि देश में जारी कोरोना टीकाकरण अभियान का दायदा धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा और सभी को निशुल्क टीका लगाया जाएगा। हसीना ने मंत्रालयों के वार्षिक निष्पादन समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद कहा कि सरकार सभी नागरिकों के नि:शुल्क टीकाकरण अभियान पर कार्य कर रही है।

पीओके की चुनावी रैली में साधा निशाना

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) में आयोजित एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) पर निशाना साधा तथा साथ ही खुद को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीरियों का 'ब्रांड एम्बेसडर' बताया। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इमरान ने पीओके के आगामी चुनावों से पहले हुई जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा और आएसएस की विचारधारा भारत के लिए ख़तरा है, क्योंकि यह विचारधारा न केवल मुस्लिम, बल्कि सिख, इसाई और एससीएसटी को निशाना बनाती है।

राजनीतिक समझौते के पक्ष में तालिबान

काबुल : अफग़ानिस्तान में जारी जंग के बीच दोहा में चल रही वार्ता के शुरू होने के बाद तालिबान के सुर बदल रहे हैं। तालिबान के सुप्रीम नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने कहा कि वे मौजूदा संघर्ष को रोकने के लिए राजनीतिक समझौते का पुरज़ोर समर्थन करते हैं। वार्ता का पहला दौर शुरू होने के बाद अब इस बात की संभावना बढ़ रही है कि हिंसा के वर्तमान हालात में समझौते की कोई राह निकल सकती है। इसको लेकर तालिबान ने भी सकारात्मक संदेश दिया है।

पाक में आटा-चीनी की कीमतें भी बढ़ीं

पेट्रोल-डीजल के बाद पाकिस्तान में अब चीनी, गेहूं के आटे, घी समेत खाने पीने की चीजों के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। इस बीच पीएम इमरान ख़ान ने गुलाम कश्मीर में चुनावी रैली के दौरान कहा कि पिछली सरकारों ने देश को अपने पैरों पर खड़े करने के बजाय हमेशा ही सहायता और कर्ज़ लेने पर ही भरोसा किया हैं जबकि कोई भी देश भीख का कटोरा लेकर कभी भी महान नहीं बन सकता। कैबिनेट की आर्थिक समनव्य समिति ने पाकिस्तान के यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में चीनी, गेहूं का आटा और घी की दरों में वृद्धि को मंज़ूरी दे दी।

इंटरनेट की टूटती साँसें

संजय वर्मा

शायद ही कोई इससे इंकार करे कि दुनिया आज जिस मुक़ाम पर है, उसमें तकनीक की अहम भूमिका है। उसमें भी इंटरनेट शीर्ष पर है। कोरोना काल में इंटरनेट ने तकरीबन पुरी दुनिया की गति को थामे रखा। पर जो तकनीक दुनिया को चला रही है, क्या वह हमेशा इसी तरह चलती और आगे बढ़ती रहेगी? अरसे से दावा किया जा रहा है कि एक दिन इंटरनेट का रुक जाना सांसें थम जाने जैसा होगा। हो सकता है कि यह दावा कपोल कल्पित लगे, पर इधर एक घटना से इस ख़तरे का अहसास करा दिया है।

कुछ ही दिन पहले, 8 जून, 2021 को दुनिया की हज़ारों छोटी बड़ी वेबसाइटों ने अचानक काम करना बंद कर दिया। इनमें कई समाचार पत्रों की वेबसाइटें भी थीं। ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन की वेबसाइटों का संचालन एक घंटे के लिए थम गया। इतनी सी देर में कंपनियों को लाखों डॉलर की चपत लग गई। जांच पड़ताल में पता चला कि एक मामूली सी गड़बड़ी इसके लिए ज़िम्मेदार थी। गड़बड़ी विभिन्न वेबसाइटों के डाटा को दुनिया भर में आवाजाही के लिए सर्वर उपलब्ध कराने वाली एक कंपनी में पैदा हुई थी। यह अमेरिकी कंपनी असल में क्लाउड सेवा प्रदाता 'फास्टनी' है। इसका काम बिना तारों के संजाल के तकनीक के बादलों पर डाटा को यहां से वहां प्रयोगकर्ताओं तक पहुंचाना है। यह कंपनी अपने सर्वर पर सेवाएं लेने वाली कंपनियों की वेबसाइटों का कुछ डाटा सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के पीछे कंपनियों की वेबसाइटों की गति को बढ़ाना है। यानि दुनिया में कभी भी इनकी वेबसाइटों को खोला जाए तो उन पर तेज़ और आसान सर्फिंग हो सकें। लेकिन जो कंपनी वेबसाइटों को गति प्रदान कर रही है, उसके यहां हुई मामूली गड़बड़ी ने महज़ एक घंटे में लाखों डॉलर के कारोबार का भट्टा बैठा दिया। यह तो सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी का मामला था। इसे आसानी से सुलझा लिया गया, लेकिन अगर इसमें साइबर सेंधमारों की भूमिका शामिल हो जाए, कुछ शत्रु देश ग़लत मंशा से कोई गड़बड़ी का मामला था। इसे आसानी से सुलझा लिया गया, लेकिन अगर इसमें साइबर सेंधमारों की भूमिका शामिल हो जाए, कुछ शत्रु देश ग़लत मंशा से कोई गड़बड़ी पैदा करने लगें तो इंटरनेट को तबाही से कैसे बचाया जा सकेगा।

फिलहाल इस प्रश्न का उचित उत्तर शायद ही किसी के पास हो। बड़ी कंपनियां तो फिर भी कुछ छोटे मोटे व्यवधान झेल सकती हैं, लेकिन उन हज़ारों लाखों छोटी कंपनियों के कामकाज का क्या होगा, जिनके लिए इंटरनेट का कुछ समय के लिए रुकना भी घातक साबित हो सकता है। फर्ज़ कीजिए, आगे चल कर अस्पतालों में मरीज़ों को ऑक्सीजन आपूर्ति करने का काम आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और इंटरनेट पर आधारित व्यवस्था के हवाले कर दिया जाता है और अचानक किसी क्षण इंटरनेट काम करना बंद कर देता है। ऐसे में होने वाली क्षति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सर्विस प्रोवाइडर फास्टली के हादसे ने इंटरनेट के एक नए मर्ज़ की ओर भी इशारा किया है। असल में, इंटरनेट की सहूलियत के कारण बहुत सा कामकाज गिनी चुनी कंपनियों के ज़िम्मे हो गया है। बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपनी वेबसाइटों की देख रेख आदि का काम चुनिंदा कंपनियों के हवाले कर रही है।। ऐसी कंपनियों के पास न तो ज़्यादा कर्मचारी होते हैं और न ही कोई बड़ा आधारभूत ढांचा। यानि जिस तरह एक कमरे में बैठकर इंटरेनट की बदौलत हज़ारों कंपनियां बनाई और चलाई जा रही हैं, उसी तरह बेहद कम संसाधनों से इंटरनेट के संचालन और देख रेख का काम भी किया जा रहा है। इससे यह दृश्य कभी भी उपस्थित हो सकता है कि एक कंपनी में हुई सामान्य सी गड़बड़ी पूरे इंटरनेट के ढांचे को बिगाड़ दे। इंटरनेट के भारी भरकम साम्राज्य के सामने मौजूद संकटों में से यह सिर्फ एक उदाहरण है। ख़तरे तो और भी हैं, जिनके संकेत अक्सर मिलते रहते हैं।

इंटरनेट की गति में व्यवधान डालने वाली घटनाओं को अक्सर इंटरनेट शटडाउन कहा जाता हैं। शट डाउन की बारंबारता हाल में सालों में काफी बढ़ी हैं। मसलन, पिछले वर्ष 14 दिसंबर को गूगल की कई सेवाएं एक घंटे के लिए ठप्प पड़ गई थीं। दुनियाभर में गूगल और उसकी अन्य सेवाओं से जुड़े उपभोक्ताओं को कंप्यूटर और मोबाईल स्क्रीन पर सेवा के अस्थायी रूप से प्रभावित होने का संदेश मिला था। बताया गया कि गूगल के सर्वर में आई गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ। बीते सालों में ऐसी घटनाएं बढ़ती गई है। कभी सर्वर फेल हो जाता है, तो कभी समुद्र के नीचे मौजूद इंटरनेट केबल कट जाता है।

इंटरनेट की गति में व्यवधान डालने वाली घटनाओं को अक्सर इंटरनेट शटडाउन कहा जाता हैं। शट डाउन की बारंबारता हाल में सालों में काफी बढ़ी हैं। मसलन, पिछले वर्ष 14 दिसंबर को गूगल की कई सेवाएं एक घंटे के लिए ठप्प पड़ गई थीं। दुनियाभर में गूगल और उसकी अन्य सेवाओं से जुड़े उपभोक्ताओं को कंप्यूटर और मोबाईल स्क्रीन पर सेवा के अस्थायी रूप से प्रभावित होने का संदेश मिला था। बताया गया कि गूगल के सर्वर में आई गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ। बीते सालों में ऐसी घटनाएं बढ़ती गई है। कभी सर्वर फेल हो जाता है, तो कभी समुद्र के नीचे मौजूद इंटरनेट केबल कट जाता है।

साइबर हमलों की निरंतरता ने अलग से चिंता पैदा कर दी है। इसी से यह आशंका जोर पकड़ने लगी है कि किसी दिन ऐसा हो सकता है कि इंटरनेट पूरी तरह बैठ जाए और तब दुनिया में लॉकडाउन से ज़्यादा बड़ी समस्या इंटरनेट के शट डाउन से पैदा हो जाए। सर्वर का बैठ जाना अब इसलिए आम है कि दुनिया में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। इससे डाटा के रूप में सूचनाओं का प्रवाह सुनिश्चित करने वाले सर्वरों पर बोझ उनकी क्षमता से कई गुना ज़्यादा है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि साइबर सेंधमारों यानि हैकरों की नज़र भी इन सर्वरों पर रहती है, ताकि वहां से डाटा चुरा सकें और मनचाहा खेल कर सकें। ऐसे में सर्वरों पर साबर हमले का खतरा लगातार बना रहता है।

बीते तीन दशकों में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या और विभिन्न कामकाज के लिए हमारी इस तकनीक पर निर्भरता – दोनों में भारी अनुपात में इजाफा हुआ है। आंकलन कहता है कि ढाई दशक पहले 1995 में दुनिया की आबादी का सिर्फ एक प्रतिशत हिस्सा इंटरनेट से जुड़ा हुआ था लेकिन अब तो साढ़े चार से पांच अरब आबादी इंटरनेट की सक्रिय उपभोक्ता है। आज की तारीख़ में करीब साठ प्रतिशत आबादी किसी न किसी रूप में इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है। भारत में करीब उनसठ करोड़ और पड़ोसी चीन में पचासी करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगे हैं। यानि पूरी दुनिया में खरीद-फरोख़्त, पढ़ाई, टीकाकरण, परीक्षा, सरकारी योजनाओं का पंजीकरण और भी बहुत सारा काम इंटरनेट से हो रहा है। ऐसे में अगर किसी वजह से इंटरनेट की सांसें थमती हैं, तो नज़ारा सच में काफी भयावह हो सकता है।

चार वर्ष पहले 2017 में अमेरिकी विश्वविद्यालय स्टैनफोर्ड के शोधकर्ता और मनोवैज्ञानिक जेफ हैनकॉक ने विश्वविद्यालय के छात्रों के सामने इंटरनेट शटडाउन की स्थितियां सामने रखीं थी, तो निष्कर्ष यह निकला कि ऐसे हालात में उन्हें कुछ अशुभ घटित होने जैसा अहसास होगा। मानो किसी ने हमारे सिर पर बम फोड़ दिया हो, क्योंकि दुनिया से पूरी तरह कट जाने के बाद हरेक व्यक्ति को यह अहसास हो सकता है कि वह किसी निर्जन द्वीप पर अकेला फंस गया और निरूपाय हो गया है।

प्रश्न है कि इंटरनेट शटडाउन से कैसे निपटा जाए। ज़ाहिर है कि तकनीक के मामले में पीछे लौटने की कोई संभावना अब नहीं है। ज़्यादा अच्छा रास्ता यह है कि इंटरनेट के संचालन में आ रही बाधाओं को दूर करने के तरीके ईजाद किए जाएं। जैसे सर्वरों की संख्या बढ़ाई जाए, इंटरनेट की हीलियम गुब्बारों की सहायता से दूरदराज़ के इलाकों तक पहुंचाया जाए, उपग्रहों के ज़रिए उनकी रफ्तार बढ़ाई जाए। साथ में वे कमियां भी दूर की जाएं, जहां से हैकरों को इसमें सेंध लगाने की कोई गुंजाइश दिखती है जिन तकनीकों के सहारे इंटरनेट यहां तक पहुंचा है, उन्हीं तकनीकों से इसके रास्तों पर रोशनी भी बिखेरी जा सकती है। ❑❑

शराब की बिक्री से किसका भला होगा?

विजय गोयल

जो सरकार कोरोना महामारी के दौरान लोगों तक दवा नहीं पहुंचा पाई, वह लोगों के घर शराब पहुंचाएगी। दिल्ली सरकार का इसके पीछे तर्क है कि इससे लोग महामारी के दौरान शराब की दुकानों पर लाइन लगाने से बच जाएंगे, शराब की बिक्री बढ़ने से सरकार की आमदनी बढ़ेगी, उससे दिल्लीवासियों की सेवा क जाएगी। सरकार को शराब से आमदनी बढ़ाने की चिंता है लेकिन दिल्ली में तेजी से पैर पसारती नशे की लत पर लगाम लगाने की फुरसत नहीं है। नई आबकारी नीति में शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए 838 पुरानी दुकानों को बंद करके नई दुकानें खोली जा रही है। दिल्ली सरकार को शराब से पांच हज़ार करोड़ रुपए राजस्व मिल रहा है। मार्च, 2021 में जब नई आबकारी नीति दिल्ली सरकार ले आई, जिसमें अन्य बदलावों के साथ-साथ शराब खरीदने वालों की उम्र पच्चीस साल से घटा कर इक्कीस साल करना तय किया, तब सरकार का अनुमान था कि इस नई आबकारी नीति से शराब से आमदनी करीब दो हज़ार करोड़ रुपए बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ मद्य निषेधालय का बजट घटा कर एक करोड़ रुपये कर दिया गया हैं अगर शराब की बिक्री को ही प्राथमिकता देना है तो मद्य निषेधालय को बंद ही कर देना चाहिए। जबकि पहले यह तय था कि शराब से होने वाली आमदनी का एक प्रतिशत शराब के ख़िलाफ़ प्रचार प्रसार पर ख़र्च किया जाएगा।

पहले शहर में जगह-जगह महात्मा गांधी के होर्डिंग्स लगाए जाते थे, जिन पर गांधीजी का कथन 'शराब शरीर और आत्मा दोनों का नाश करती है' लिखा होता था। महात्मा गांधी ने कहा था कि साध्य के लिए किस संसाधन का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका उसके परिणाम पर सीधा असर होता है। शराब घर-घर पहुंचा कर लोगों को बीमार बना कर उनके घरों की पूंजी का इस कोरोना महामारी के संकट में शराब की भेंट चढ़ाकर सरकार कैसा समाज बना रही है? देश में मद्यनिषेध के आंदोलन चलाए गए। लोगों ने कहा कि हमें शराब नहीं शिक्षा चाहिए। आबकारी नीति में मंदिर और दूसरे धर्मस्थल या स्कूल के सौ गज़ के दायरे में शराब की दुकान खोलने पर पाबंदी है। अब अब घर-घर शराब पहुंचाई जाएगी तो इस तरह की पाबंदी का क्या मतलब रह गया है। आरोप है कि कुछ शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने शराब की होम डिलिवरी का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि शराब घर घर पहुंचाने से बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसी तरह के बेतुके तर्क सालों पहले तब दिए जाते थे, हम हमारी 'लोक अभियान' संस्था 'लॉटरी' बंद करने का आंदोलन चला रही थी। तब कहा जा रहा था कि लॉटरी बंद होने से हजारों लोगों का रोज़गार चला जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार को लॉटरी से काफी राजस्व मिलता है, उससे जन उपयोगी काम कराए जाते हैं। 1997 में तब के प्रधानमंत्री इन्दर कुमार गुजराल ने लॉटरी बंद करने के लिए अध्यादेश जारी कराया और 1998 में केन्द्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने संसद में विधेयक लाकर लॉटरी को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया।

अगर राजस्व अर्जित करने का ही सवाल होता, तो महात्मा गांधी के गृहराज्य गुजरात में शराब पर स्थायी पाबंदी नहीं लगती। बिहार जैसे पिछड़े राज्य की राजग सरकार ने अप्रैल 2016 से शराब पर पाबंदी लगा दी। लोग राज्य की तंगहाली और शराब की तस्करी आदि के आधार पर शराबबंदी हटाने की मांग करते रहे, लेकिन सरकार ने अपना इरादा नहीं बदला। हरियाणा में भी चौधरी बंशीलाल ने शराबबंदी की थी, लेकिन शराब माफिया ने उसे सफल नहीं होने दिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना के प्रसार के प्रसार में नशे की भी भूमिका है। ख़ुद सरकार ने पिछले साल कोरोना महामारी के दौरान 05, मई 2020 को शराब पर सत्तर प्रतिशत उपकर लगा दिया था। लेकिन महीनेभर में ही 9 जून, 2020 को उसे हटाकर जीएसटी को बीस से बढ़ाकर पच्चीस प्रतिशत कर दिया। इससे शराब पड़ोसी राज्यों के मुक़ाबले सस्ती हो गई और दिल्ली में इसकी बिक्री बढ़ गई।

कुछ साल पहले भी शराब की होम डिलिवरी की सुविधा दी गई थी, लेकिन उसके लिए साधन तय न करने से वह योजना सिरे नहीं चढ़ पाई। इस बार सरकार ने इसे लोकप्रिय बनाने के लिए शराब का होम डिलिवरी ऐप शुरू किया है, जिसके ज़रिए ऑनलाइन बुक कराया जा सकता है, जैसे घर के अन्य सामान इंटरनेट से बुक करा कर मंगाए जाते हैं। तर्क दिया जा रहा है कि बहुत सारे लोग लंबी लाइन और भीड़ के चलते शराब की दुकानों पर न जाकर ब्लैक में शराब खरीदते हैं। उन्हें दुकान पर लेने में झिजक होती है। संभव है, कुछ युवाओं का इस योजना का समर्थन मिले, लेकिन घर की महिलाओं से पता करें कि उन पर शराब का प्रसार बढ़ने से क्या बीतेगी।

कुछ साल पहले भी शराब की होम डिलिवरी की सुविधा दी गई थी, लेकिन उसके लिए साधन तय न करने से वह योजना सिरे नहीं चढ़ पाई। इस बार सरकार ने इसे लोकप्रिय बनाने के लिए शराब का होम डिलिवरी ऐप्प शुरू किया है, जिसके ज़रिए ऑनलाइन बुक कराया जा सकता है, जैसे घर के अन्य सामान इंटरनेट से बुक करा कर मंगाए जाते हैं। तर्क दिया जा रहा है कि बहुत सारे लोग लंबी लाइन और भीड़ के चलते शराब की दुकानों पर न जाकर ब्लैक में शराब खरीदते हैं। उन्हें दुकान पर लेने में झिजक होती है। संभव है, कुछ युवाओं का इस योजना का समर्थन मिले, लेकिन घर की महिलाओं से पता करें कि उन पर शराब का प्रसार बढ़ने से क्या बीतेगी। यह कौन तय करेगा कि इस शराब के साथ देसी और मिलावटी शराब न घरों में पहुंचाई जाए। मिलावटी शराब से आए दिन लोगों के मरने की ख़बर आती है। अभी तक बहुत सारे लोग घर वालों से छिपकर या कभी-कभार शराब पीते थे। अब वे आसानी से हर रोज़ घर पर मंगा कर शराब पीने लगेंगे। जो शराब डिलिवरी मैन लेकर आएंगे उन पर क्या दिल्ली सरकार की मुहर लगी होगी कि उस शराब के साथ पीने से लोग बीमारी होंगे तो उसकी ज़िम्मेदारी किसकी होगी। इस बात की सरकार गारंटी लेगी कि इससे जो आमदनी होगी उसका उपयोग सरकार अपने प्रचार में रुपया फूंकने के बजाय जन सेवा के लिए करेगी। जब कोरोना से संक्रमण दर बत्तीस प्रतिशत था, तब कोई विज्ञापन नहीं आया था, अब संक्रमण दर एक प्रतिशत हो गया है, तो अख़बारों में हेल्पलाइन के होर्डिंग्स जारी किए है। कोरोना बंदी या लॉकडाउन में शराब की बिक्री जारी रखने का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, सरकारी कभी इसका सही आंकलन करेगी? जब कोरोना मरीज़ों की संख्या हर रोज़ तीन हजार के पार चली गई थी और अस्पतालों में ऑक्सीजन से लेकर भर्ती होने के लिए अफरातफरी मची थी, तब तो सरकार लोगों के घरों में दवा या दूसरे ज़रूरी सामान भिजवाना तो दूर, कोरोना से जुड़ी सूचना तक नहीं भिजवा पा रही थी। तब दवाओं की होम डिलीवरी नहीं सूझी।

इस कोरोना काल में सरकार की चिंता लोगों के रोज़गार बचाने की होनी चाहिए। उनकी जान बचाने के साथ-साथ उन्हें स्वस्थ रखने के प्रयत्न करने चाहिए। पर हैरानी है कि सरकार शराब से आमदनी बढ़ाने में लगी हुई है। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उसकी तीसरी लहर आने की आशंका है। कोरोना के बाद लोग 'ब्लैक फंगस' से प्रभावित हो रहे हैं। लोगों ने अपने जीवन की गाढ़ी कमाई संकट के समय अपने और अपने अपनों को बचाने के लिए जोड़ रखी होगी, सरकार उन्हें देने के बजाय शराब जैसी बुराई की भेंट चढ़ाने का एक और काम कर रही है। दिल्ली को विश्वस्तरीय शहर बनाने का दावा करने वाली सरकार इसे शराब में डूबोने में लगी है। कायदे में तो दिल्ली जैसे छोटे राज्य, जहां राजस्व के काफी बड़े स्रोत पहले से मज़बूत हैं, उसे और बेहतर बनाकर दिल्ली को शराब रहित दुनिया की सबसे बढ़िया राजधानी बनाना चाहिए। ❑❑

कर्नाटक सी.एम. येदियुरप्प के उत्तराधिकारी पर सस्पैंस, 16 अगस्त तक दे सकते हैं इस्तीफा

भाजपा में इन दिनों सी.एम. तबादला/फेरबदल चल रहा है, पता नहीं किस दिन किस मुख्यमंत्री का फेरबदल हो जाए, पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर अटकलें लग रही थीं हालांकि दिल्ली के अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद येदियुरप्पा ने अपने इस्तीफे की ख़बरों को खारिज कर दिया। अब बी.एस. येदियुरप्पा चौथी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के ठीक 2 वर्ष बाद 26 जुलाई को भाजपा विधायक दल की बैठक कर रहे हैं। इससे भाजपा हलकों में अटकलें तेज हो गई हैं।

नेताओं का कहना है कि ये टिप्पणियां भाजपा के 75 वर्ष से ऊपर के मंत्रियों को नहीं रखने की स्थिति के विपरीत है। चूंकि पार्टी अगले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों का सामना करने के लिए तैयार है इसलिए कर्नाटक से जुड़े फैसले को आगे बढ़ाने की अभी संभावना नहीं है। पार्टी का एक अन्य ग्रुप 78 वर्षीय इस सी.एम. को उनकी आयु को देखते हुए हटाने की मांग कर रहा है और 2023 के विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री का नया चेहरा पेश करने की ज़रूरत पर ज़ोर दे रहा है।

ख़ास ख़बरें

श्रीलंका संसद में उठा भारत की खुफिया सूचना का मुद्दा

कोलंबो : श्रीलंका में 2019 में ईस्टर पर आत्मघाती बम धमाकों को लेकर भारत द्वारा उपलब्ध कराई गई खुफिया सूचना पर कार्रवाई करने में नाकाम रहने का मुद्दा पूर्व पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने संसद में उठाया। इस हमले में 11 भारतीयों समेत 270 लोग मारे गए थे। विक्रमासिंघे ने कहा कि उस समय एक मंत्री हरीन फर्नांडो ने उन्हें हमलों के बाद कहा था कि फर्नांडो के पिता ने उनकी बहन को ईस्टर प्रार्थना में शामिल न होने की चेतावनी दी थी क्योंकि उस दिन वहां कुछ बुरा होना था।

द० कोरियाई सेना पर कोरोना हमला

सियोल : कोरोना वायरस ने दक्षिण कोरिया की सेना के जंगी जहाज़ पर हमला बोल 251 सैनिकों को अपनी चपेट में ले लिया हैं दक्षिण कोरिया के ज्वाईंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल वॉन इन चाउल ने बताया कि अदन की खाड़ी में जंगी जहाज पर मौजूद 80 प्रतिशत सदस्य संक्रमण की चपेट में आ गए हैं सेना के 301 सैनिकों में से सिर्फ 50 सुरक्षित है।

गोसन को भगाने पर अमेरिकी पिता पुत्र को जापान में सज़ा

टोक्यो : जापान की एक अदालत ने 'निसान' कंपनी के पूर्व अध्यक्ष कार्लोस गोसन को भगाने में मदद को लेकर अमेरिकी सेना के विशेष बल के दिग्गज माइकल टेलर को दो वर्ष और उसके बेटे को एक वर्ष आठ माह की क़ैद की सज़ा सुनाई हैं कार्लोस गोसन भ्रष्टाचार के आरोप में नज़रबंद थे जिन्हें निजी जेट के बक्से में छिपाकर भगाने के लिए दोनों अमेरिकियों को मैसाचुसेट्स की एक जेल में रखा गया है।

इराक : राजधानी बग़दाद में बम धमाका 25 की मौत

बग़दाद : इराक़ की राजधानी बग़दाद के सद्र शहर में भीड़भाड़ वाले वहैलात बाजार को निशाना बनाकर सड़क के किनारे किए गए बम धमाके में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई। घटना में दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। इराक़ की सेना ने बताया कि ईदुल अज़्हा त्यौहार की छुट्टी के एक दिन पहले हुए इस धमाके के दौरान बाजार में खरीदारी करने वालों की भीड़ थी। धमाके की ज़िम्मेदारी अब तक किसी संगठन ने नहीं ली है। घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

औरंगज़ेब आलमगीर रह॰ की वसीअुल नज़री की दास्तान

डाक्टर बी॰ बेगम मोधा

तारीख़ (इतिहास) का गहरा मुताअला करने के बाद यह पता चलता है कि इस मुल्क़ में अकबर ने हुकूमत के मामले में जिस वसीअ नज़री और बे-तास्सुबी का मज़ाहिरा किया है, शहंशाह औरंगज़ेब भी इस पर सख़्ती के साथ अमल करता रहा है ओर इसका अंदाज़ा इस से हो सकता है कि अगर अकबर के ज़माने में हफ्त-हजारी से लेकर यक हज़ारी तक कुल 25 हिन्दू ओहदेदार थे तो औरंगज़ेब के ज़माने में उनकी तादाद 70 तक पहुंच गयी थी। यह बात भी फरामोश नहीं करनी चाहिए कि यह सब सफ-अव्वल के ओहदेदार थे, दरजा दोम और सोम के ओहदेदारों की तादाद अनगिनत है।

ख़ुद ग़ैर मुस्लिम लेखकों ने औरंगज़ेब की बेताअस्सुबी की बेहद तारीफ़ की है इसलिए प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं कि ''परमात्माई शान है कि औरंगज़ेब जितना वसीअ नज़र और अपनी रिआया का ख़ैर ख़्वाहा था उतना ही उसे बदनाम किया गया है, कोई उसे ज़ालिम कहता है तो कोई खूनी लेकिन हक़ीक़त में वह आलमगीर के लक़ब का मुस्तहिक़ था। औरंगज़ेब के काल के अंग्रेज़ पर्यटक कप्तान हेमलटन का बयान है कि ''औरंगज़ेब की हुकूमत का मज़हब अगरचे इस्लाम है लेकिन संख्या में अगर दस हिन्दू हैं तो एक मुसलमान है। हिन्दुओं के साथ मज़हबी रवादारी पूरे तौर पर बरती जाती है। वह अपने व्रत रखते हैं, पूजा पाट करते हैं और इसी तरह त्यौहार मनाते हैं, जैसे अगले ज़माने में मनाते थे।'' हिन्दोस्तान के पहले राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद औरंगज़ेब की बेतआस्सुबी का तज़करा करते हुए लिखते हैं, औरंगज़ेब ने गिरधर वल्द जगजीवन साकिन मौज़ा बस्ती ज़िला बनारस जदू मिश्र साकिन महेशपुरा और पंडित बाल भद्र मिश्र को जो तीनों मेहंत थे, मन्दिरों के लिए जागीरें दी थीं'' यह हैं औरंगज़ेब के बारे में ग़ैर मुस्लिम मुदब्बिरीन के ख़्यालात।

मुफ्ती शौक़त अली फहमी अपनी तारीख़ हिन्दोस्तान पर मुग़लिया हुकूमत में लिखते हैं कि औरंगज़ेब की हिन्दू दुश्मनी के इल्ज़ाम की असल हक़ीक़त का अंदाज़ा इस से लगाया जा सकता है कि इसका सब से बड़ा फौजी सिपहसालाहार राजा जय सिंह था जब तक जयसिंह ज़िन्दा रहा उसने फौजी मामलात में इस हिन्दू जनरल के मुक़ाबले में न किसी मुस्लिम सिपहसालार का ऐतबार किया और न अपनी औलाद का, औरंगज़ेब ने काबुल जैसा अहम सूबा राजा जसवंत सिंह के सुपुर्द कर रखा था जहां सौ प्रतिशत कट्टर मुसलमान आबाद थे क्या कोई मुतसिब बादशाह ऐसा कर सकता है।

औरंगज़ेब ने मौहम्मद मोअज़्ज़म की शादी खुद हिन्दू राजा की लड़की से की थी। ख़ुद शहज़ादा मोअज़्ज़म की मां राजपूतनी थी, मगर उसे कभी मुसलमान होने तक को नहीं कहा गया औरंगज़ेब ने राय मकर नद राय को रुहेलखण्ड का गवर्नर बनाया था। इस के बाद उसे भारत के सबसे बड़े सूबे बंगाल का गवर्नर बनाया। निज़ामउल मुल्क को बर्खास्त करके औरंगज़ेब ने गिरधर राय को मालवा का गवर्नर बनाया था, राजा किशन काबुल का गवर्नर था। राय-रायान राजा रघुनाथ सिंह सल्तनत का मदारुल महारम था जो सबसे बड़ा दर्जा होता है, मानसिंह हाड़ा इसका फौजी मुशीर था राय लाल चन्द शाही दीवान का हाकिम आला था जिसे आलमगीर ने माली मुक़दमात का फैसला करने के लिए क़ाबुल में मामूर किया था, राजा ओदत नारायण सिंह सह हज़ारी और हज़ारों सवार

औरंगज़ेब ने मौहम्मद मोअज़्ज़म की शादी खुद हिन्दू राजा की लड़की से की थी। ख़ुद शहज़ादा मोअज़्ज़म की मां राजपूतनी थी, मगर उसे कभी मुसलमान होने तक को नहीं कहा गया औरंगज़ेब ने राय मकर नद राय को रुहेलखण्ड का गवर्नर बनाया था। इस के बाद उसे बंगाल का गवर्नर बनाया। निज़ामुल्क को बर्खास्त करके औरंगज़ेब ने गिरधर राय को मालवा का गवर्नर बनाया था, राजा किशन काबुल का गवर्नर था।

पर अफसर आला था जिसे बाद में ईरान का फौजदारी हाकिम बनाया गया था।

आलमगीर का शहज़ादा मौहम्मद आज़म जब उज्जैन का गवर्नर था, तब तलूक चन्द इसका दीवान व मुशीर आला था चौरामन जाट को भरतपुर की जागीर दी गयी जो अब तक चली आती है। इसके लड़के बदन सिंह को भी अलग से जागीर दी गयी थी। आलमगीर ने नवान्गर का पूरा इंतज़ाम तमाची के सुपुर्द कर दिया था और उसके खानदान के कई लोगों को बड़ी-बड़ी जागीरें अता की थीं। जसवंत सिंह झाला को हलूद का राजा बनाया था, और इस्टेट दी थी परगना मनूरी जो बलूचो की जागीर थी यह सुंदर सिंह व नौगन और हयाजी राव को दी गयी थी, गिरधर दास सिसौदिया को दिल्ली का हाकिम आला बनाया गया था, राजा आलम सिंह को उज्जैन की ज़मीनदारी देकर उज्जेन का वज़ीर बना दिया गया था। देवेन्द्र राव को दो हज़ारी मंसब दिया गया था। और कोहमहा देव को कोतवाल बनाया गया था। परथी सिंह को गढ़हवाल की इस्टेट दी गयी थी। मुकुल राय को नुसरताबाद का नाज़िम आला मुक़र्रर किया गया था। शिवभान राय को पंचहज़ारी मंसब दिया गया, यह पहले सितारा का क़िलेदार था। जो शिवाजी का चचेरा भाई था सह-हज़ारी मंसब पर था और दो हज़ार पांच सौ सवारों का हाकिम, अचला ची मराठा शिवाजी का दामाद था उसे पंच हजारी मंसब पर और दो हज़ार सवारों के ऊपर हाकिम आला मुक़र्रर किया गया था। बसंत राव मराठा चार हज़ार मंसब पर और चार हजार सवारों पर अफसर था, शिवा लाल शश हज़ारी था और पांच हज़ार सवारों की कमान करता था, राजा मांधाता को ग़ौरनंद का कोतवाल बनाया गया था, राघूदास झाला को हफ्त सदी मंसब और पांच सौ सवारों पर अफसर मुक़र्रर किया गया था। बिक्रम सिंह ग्वालियरी को दो हज़ार पांच सदी के मंसब पर हाकिम बनाया गया था। अरजो जी जो शम्भा जी का चचेरा भाई था दो हज़ारी मंसब और दो हज़ार सवार कमांडर था व मुरलीधर आलमगीर का एडवाइज़र था, भागूमल पंच हज़ारी मंसब और पांच हज़ार सवारों का कमांडरिंग ऑफिसर था। दुर्गादास राठौर दो हज़ारी मंसब पर फाइज़ था। राजा कल्याण दास भदौरिया यक हज़ारी मंसब पर मामूर था। राजा बिशन सिंह को आलमगीर ने मथुरा का हाकिम फौजदारी और पांच सवारों का हाकिम बनाया था। राजा जय सिंह जिन्होंने जयपुर शहर आबाद किया, एक बड़े सिविल हाकिम थे राजा विजय सिंह और राजा राय सिंह राठौर आलमगीरी अमीर थे।

राजा इन्द्र सिंह राठौर को औरंगज़ेब आलमगीर ने जोधपुर इस्टेट अता की थी, राजा अनरूद्ध सिंह को आलमगीर ने बूंदी की हकूमत दी थी ओर इंतज़ाम के लिए बड़ी रक़म खज़ाने से दी थी जगत सिंह हाड़ा को कोटा की जागीर दी थी। राजा अनूप सिंह को औरंगज़ेब का गवर्नर मुक़र्रर किया गया था राजा सरूप सिंह को बीकानेर की हुकूमत अता की गयी थी, राव शुभकरण बुंदेला सिंह को आलमगीर ने शिवाजी के मुक़ाबले में बीजापुर की मुहिम में नामूर किया था। राजा देबी सिंह को भलसा की फौजदारी का हाकिम आला बनाया गया था। राना राज सिंह जो महाराणा प्रताप सिंह का पड़पौता था इसको पंच हज़ारी मंसब दिया गया और उदयपुर की इस्टेट

बाक़ी पेज 11 पर

नूरे क़ुरआन

(सूरा अल शम्श नं॰ 91)

अनुवाद और व्याख्या : शैख़ुल हिन्द र.अ.

यह सूरा मक्का में उतरी इसमें पन्द्रह आयते हैं।

प्रारंभ करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो असीम कृपालु महादयालु है।

क़सम है सूरज की और उसकी धूप चढ़ने की और चाँद की जब सूरज के पीछे आये।

अर्थात् सूरज छुपने के पश्चात् जब उसकी चाँदनी फैले।

और दिन की जब वह उसको ख़ूब प्रकाशित कर दे।

अर्थात् जब दिन में सूरज पूरी रोशनी और सफाई से निकले।

और रात की जब वह उसको छिपा ले।

अर्थात् जब रात का अंधकारपूर्ण से छा जाये और सूरज की रोशनी का कुछ निशान दिखाई न दे।

और आसमान की और जैसाकि उसको बनाया।

अर्थात् जिस शान और सम्मान का उसको बनाया।

और ज़मीन की और जैसा कि उसको फैलाया।

अर्थात् जिस तात्विकता से गोल पृथ्वी को फैलाकर लोगों के रहने के योग्य बनाया।

और जान की और जैसा कि उसको ठीक बनाया।

अर्थात् हर प्रकार की योग्यता उसको दी और नेकी और बदी पर चलने की योग्यता भी उसमें रखी।

फिर उसको बुराई और परहेज़गारी की समझ दी।

अर्थात् प्रथम तो संक्षिप्त में बुद्धि और सच्चे स्वभाव के द्वारा अच्छाई व बुराई में अंतर की सूझ दी, तत्पश्चात् विस्तार रूप से रसूलों की ज़ुबानी खोल-खोलकर बतला दिया कि यह रास्ता बुराई का और यह रास्ता परहेज़गारी का है। इसके पश्चात् हृदय में जो नेकी का आकर्षण या बुराई को ग्रहण करने की इच्छा होती है, उन दोनों का उत्पन्न करने वाला भी अल्लाह है, यद्यपि प्रथम कार्य में फरिश्ता माध्यम होता है और दूसरे में शैतान। फिर वह आकर्षण कभी बन्दे के इरादे और अधिकार से दृढ़ विचार तक पहुंचकर कार्य करने का कारण बन जाता है। जिसका पैदा करने वाला तो अल्लाह ही है, लेकिन अपने अधिकार से कार्य रूप में लाने वाला बन्दा है। इसी अधिकार से अच्छाई और बुराई को कार्य रूप देने पर इंसान को अच्छा और बुरा बदला दिया जायेगा।

निश्चय ही वह सफल हो गया जिसने उसको संवार लिया।

मन का संवारना और पवित्र करना यह है कि अभिलाशाओं और क्रोध की शक्ति को बुद्धि के आधीन रखे और बुद्धि को अल्लाह के नियमों के आधीन रखें, जिससे आत्मा और हृदय दोनों अल्लाह के नूर से प्रकाशित हो जायें।

और असफल हुआ जिसने उसको मिट्टी में मिला छोड़ा।

मिट्टी में मिला छोड़ने से तात्पर्य यह है कि मन की बागडोर इच्छाओं और क्रोध के हाथ में दे दे। बुद्धि और अल्लाह के भेजे हुए नियमों से कोई संबंध न रखे, जिससे आत्मा और हृदय दोनों अल्लाह के नूर से प्रकाशित हो जायें।

और असफल हुआ जिसने उसको मिट्टी में मिला छोड़ा।

मिट्टी में मिला छोड़ने से तात्पर्य यह है कि मन की बागडोर इच्छाओं और क्रोध के हाथ में दे दे। बुद्धि और अल्लाह के भेजे हुए नियमों से कोई संबंध न रखे, अर्थात् इच्छाओं और लालच के आधीन रहकर मन का दास बन जाये। ऐसा व्यक्ति पशुओं से भी बुरा और अपमानित है।

फ़रिश्ते को नबी क्यों नहीं बनाया गया?

दुनिया में किसी फ़रिश्ते को नबी बना कर नहीं भेजा गया क्योंकि वह हमारे लिए नमूना नहीं बन सकता, इस लिए कि वह तो चौबीस घंटे, महीनों और सालों इबादत में मशगूल रहेगा और वह थकेगा भी नहीं इसके बावुजूद वह अगर बुराई से बचेगा और अच्छाई करेगा तो सवाब मिलेगा, यही इम्तेहान का मतलब है, तो इसी ग़र्ज़ से अल्लाह तआला ने इंसानों ही में से अंबिया अ़लैहिमुस्सलाम को नमूना बना कर भेजा। पहले यह होता था कि अंबिया ख़ास क़ौमों की तरफ़ तशरीफ़ लाते थे, बयक वक़्त कई कई नबी होते थे, जब क़ौम में बिगाड़ होने लगता तो दूसरा आ जाता लेकिन हमारे आक़ा व मौला हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अल्लाह तआ़ला ने क़यामत तक के लिए नबी बनाकर मबऊ़स फ़रमाया, मश्रिक़ व मग़्रिब के लिए आप को नबी बनाया, जिन्नात और इंसानों के लिए आप को नबी बनाया, तमाम आलम के लिए आप ही को नुबुव्वत अता फ़रमाई क्योंकि अब कोई नया नबी दुनिया में आने वाला नहीं है, आप पर दीन को मुकम्मल कर दिया, अब आप के दीन के अलावा कोई चीज़ ज़रिया-ए-निजात नहीं है, और इंसानियत को इ़ज़्ज़त नहीं मिल सकती जब तक कि वह पैग़म्बर के तरीक़े पर न चले, न दुनिया में कामियाबी मिलेगी न आख़िरत में कामियाबी मिलेगी, यही दीने मुहम्मदी ज़िंदगी का सब से बड़ा सरमाया है, इस लिए हर मुसलमान की यह ज़िम्मेदारी है कि वह पैग़म्बर की सीरत से अपने आपको जोड़ कर रखे, जितना सीरत से क़रीब होता जायेगा, उतना ही पैग़म्बर से क़रीब हो जायेगा।

चेहरे बदले क्या चाल भी बदलेगी सरकार की

12 मंत्रियों का मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना और 36 नए मंत्रियों का शामिल होना किसी सरकार के लिए साधारण घटना नहीं है। कौन सोच सकता था कि नरेन्द्र मोदी मंत्रिमंडल के प्रमुख चेहरों रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, डॉ. हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक, सदानंद गौड़ा जैसे कद्दावर कैबिनेट मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ेगा? यह सब हुआ क्योंकि सरकार और भाजपा असाधारण परिस्थितियों से गुज़र रही है।

कुछ माह पहले तक देश और दुनिया में मोदी की छवि सफल प्रधानमंत्री की थी। लेकिन कोरोना की दूसरी हर में स्वास्थ्य ढांचा धराशायी हो गया। इससे मोदी और उनकी सरकार की देश विदेश में नकारात्मक छवि बनी है। इसमें विरोधियों को भी एक अवसर दिखा। उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए पीएम और सरकार की छवि मटियामेट करने की कोशिश की, जिसका असर भी हुआ। पीएम को 2014 से अब तक कभी ऐसी विपरीत स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था। वहीं, पश्चिम बंगाल में भाजपा और संघ समर्थकों के विरुद्ध हिंसा के कारण पार्टी में निराशा है। पहली बार भाजपा समर्थकों की ओर से सरकार पर तीखा हमला हो रहा है। तीसरी विकट स्थिति आर्थिक संकट है। इन कारणों से समाज के हर आयु और वर्ग में निराशा है।

इन हालात में मोदी और भाजपा के लिए पहली चुनौती सरकार की छवि ठीक करने की है। अगर आप मंत्रिमंडल में हुए इस व्यापक फेरबदल को देखेंगे तो उसमें सारे पारंपरिक पहलू नज़र आएंगे। मसलन, राजनीतिक और चुनावी ज़रूरतें, सामाजिक संतुलन, आयु, क्षेत्रीय संतुलन आदि। अगर उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सात नए मंत्री शामिल हुए और कुल मिलाकर अब वहां से प्रधानमंत्री को छोड़कर 14 मंत्री हैं तो इसे 2022 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जाएगा। पूर्वोत्तर से पहली बार पांच मंत्री और उसमें भी त्रिपुरा से एक मंत्री चुनावी ज़रूरतों के खांचे में फिट हो सकता है। पश्चिम बंगाल में चार मंत्रियों के चुनाव की भी यही वजह है। महाराष्ट्र का पूर्व सीएम होने के नाते नारायण राणे का कैबिनेट में आना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन शिवसेना की उनकी पृष्ठभूमि आज के संदर्भ में खास राजनीतिक मायने रखती है। गुजरात से पांच मंत्री और अपना दल की अनुप्रिया पटेल को शामिल करने के चुनावी उद्देश्य हैं।

मंत्रिमंडल में 25 प्रदेशों को प्रतिनिधित्व देकर भाजपा ने अखिल भारतीय पार्टी होने का संदेश भी दिया है, किन्तु इस विस्तार का फोकस सरकार का चेहरा बदलने पर केन्द्रित है। मोदी और शाह इस बात से नाराज़ थे कि देश विदेश के मीडिया और सोशल मीडिया में जारी सरकार विरोधी अभियानों के ख़िलाफ़ मंत्रियों और पार्टी नेताओं ने सही रणनीति नहीं अपनाई। सरकार और भाजपा की पहचान विरोधियों को आक्रामक ढंग से जवाब देने वाली रही है जो बंगाल चुनाव के बाद अचानक गायब हो गई। कोरोना संकट में तो सरकार और पार्टी जैसे लुप्त ही हो गई थी। इसे लेकर हुए मंथन का नतीजा यह निकला कि सरकार और पार्टी दोनों में चेहरा, चरित्र और कामकाज तीनों स्तरों पर व्यापक परिवर्तन के बग़ैर इतनी भारी क्षति की पूर्ति नहीं हो सकती।

अब नए चेहरों के साथ विभागों के बंटवारे को देखिए, शीर्ष मंत्रियों को छोड़ दें तो लगभग पूरी बदली हुई सरकार दिखेगी। लोग रविशंकर प्रसाद और जावड़ेकर जैसे मंत्रियों को हटाए जाने से हैरान हैं, लेकिन दोनों अपनी भूमिकाओं में चूके थे। टवीटर के साथ विवाद में जिस तरह से कानूनी पक्ष आगे बढ़ाया गया, उससे संदेश यह निकला कि एक कंपनी के सामने सरकार का इक़बार कमज़ोर पड़ रहा है। कई मामले पर्दे के पीछे से भी हैंडल किए जाते हैं। प्रसाद न्याय मंत्री भी थे, इसलिए अदालती मामलों को निपटाने की ज़िम्मेदारी भी उनकी थी।

इस बीच अदालतों की टिप्पणियां भी सरकार और पार्टी को नागवार गुज़री है। मंत्री और नेता कह रहे थे कि महाधिवक्ता से लेकर सॉलिसिटर जनरल, वकीलों, न्यायविदों की इतनी बड़ी फौज होते हुए भी सरकार का पक्ष अदालत के सामने ठीक से नहीं रखा जा रहा है। भारतीय मीडिया के साथ संवाद और सहकार की भूमिका सूचना और प्रसारण मंत्रालय की होती है। सिर्फ प्रेस कांफ्रेंस या बयान जारी करना ऐसे संकट में पर्याप्त नहीं था। मीडिया संस्थानों के प्रमुखों, छोटे-बड़े पत्रकारों, संपादकों, स्वतंत्र विश्लेषकों – टिप्पणीकारों से संवाद और संपर्क हुआ ही नहीं। डीडी न्यूज के हिंदी और अंग्रेजी दोनों चैनलों को कोरोना संकट के दौरान एक कर दिया गया और बहस ग़ायब हो गई। सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए तब इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी। दूसरी ओ, पार्टी के अंदर प्रभावी ढंग से प्रेस कांफ्रेंस में अपनी बात रखने वाले प्रवक्ताओं की भी कमी महसूस हुई। एक समय अरुण जेटली, सुषमा स्वराज जैसे नेता पार्टी के लिए भी पत्रकार वार्ता करते थे। अब रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर इसके लिए उपयुक्त हो सकते हैं।

यानि सरकार और पार्टी दोनों के स्तर पर आक्रामक मुखरता दिखेगी। आगे विधानसभा चुनावों और 2024 में लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन सरकार और पार्टी दोनों की छवि पर ही मुख्यत: निर्भर करेगा। इस सच से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि किसी भी सरकार और पार्टी की छवि सिर्फ चेहरा बदलने से ठीक नहीं हो सकती। चेहरे का महत्व है, लेकिन प्रदर्शन यानि काम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर सरकार शासन के स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करती है तो कमज़ोर चेहरे भी समर्थन पाते हैं। इसी तरह पार्टी अगर राजनीतिक मामलों में अपने चरित्र के अनुरूप भूमिका निभाती है तो कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जोश बना रहता है। मोदी सरकार अगर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में सफल हुई, भविष्य में कोरोना जैसी आपदा से निपटने के अनुरूप स्वास्थ्य ढांचा सबल दिखा, मोदी द्वारा निश्चित समयावधि में सबके लिए मकान, हर घर पानी, बिजली, हर खेत को सिंचाई और भारत को 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने जैसे लक्ष्यों के अलावा त्रुटिहीन सुरक्षा ढांचा, शिक्षा में आमूल बदलाव और धर्म संस्कृति के क्षेत्र के घोषित अघोषित भाजपा की विचारधारा वाले लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में काम हुआ तो पार्टी और समर्थक आत्मविश्वास के साथ विपरीत परिस्थितियों से राजनीतिक तौर पर निपट लेंगे। ❑❑

उत्तराखंड : धामी के ज़रिए भाजपा साधेगा कुमाऊं

उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में सबसे युवा पुष्कर सिंह धामी ने कमान संभाली है। वे 45 वर्ष के हैं। सबसे उम्रदराज़ मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी थे जो राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री थे और तिवारी पहली निर्वाचित विधानसभा के 2022 में मुख्यमंत्री बने। तीरथ सिंह रावत तो जिस दिन से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे उसी दिन से उन्हें हटाए जाने की चर्चा शुरू हो गई थी और मई के महीने में उत्तराखंड के दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने पाया कि भाजपा सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। 10 मार्च को जब तीरथ सिंह ने शपथ ली थी उसके बाद उन्हें विधानसभा का उपचुनाव करवा कर विधायक बनवा दिया जाता तो संवैधानिक संकट पैदा न होता। माना जा रहा था कि इस बार भाजपा कुमाऊं के राजपूत बिरादरी के विधायक को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा कर उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्रवाद और जातिवाद को साधने का काम करेगी इसलिए भाजपा ने इस बार क्षेत्रवाद को साधने के लिए कुमाऊं से युवा मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह को मौक़ा दिया। ये राज्य के पहले ऐसे विधायक हैं जो किसी सरकार में मंत्री नहीं रहे। वे केवल संगठन के ही व्यक्ति रहे। युवा मोर्चो के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे तथा विद्यार्थी परिषद् से जुड़े रहे हैं। वे 2011 में भगत सिंह कोश्यारी के मुख्यमंत्री बनने पर उनके विशेष कार्य अधिकारी थे।

धामी को युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में संगठन का अनुभव तो है परंतु उन्हें सरकार का अनुभव नहीं है। इस तरह वे पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो विधायक से सीधे मुख्यमंत्री बने। दरअसल भाजपा के लिए इस बार मुख्यमंत्री आठवीं बार बदलते हुए क्षेत्रवाद का विशेष ध्यान रखना था क्योंकि भाजपा ने 11 सालों में गढ़वाल से चार मुख्यमंत्री दिए और कुमाऊं से केवल भगत सिंह कोश्यारी एकमात्र राजनेता थे जिन्हें भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद भाजपा नेताओं की घोर उपेक्षा की जिससे कुमाऊं में भाजपा को लेकर गहरा असंतोष पनप रहा था। असंतोष शांत करने के लिए पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया कांग्रेस ने 10 सालों में कुमाऊं से दो मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी और हरीश रावत बनाए जबकि विजय

बाक़ी पेज 11 पर

हिमाचल प्रदेश : पार्टी की तमाम रपट में तो फिसल चुके हैं जयराम

उत्तरखंड में बेशक चार माह में ही आलाकमान ने मुख्यमंत्री बदल दिया हो लेकिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर फिलहाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बदौलत अपना पद बचाने में सफल रहे हैं। हालांकि अटकलें उन्हें भी लेकर कम नहीं है। प्रदेश में हुए चार नगर निगम के चुनावों में से जब से दो पर भाजपा की हार हुई है, तभी से अंदरखाने उनका तख़्ता पलटने की मुहिम शुरू हो गई थी। आलाकमान को तब लगा कि हिमाचल ख़तरे में आ गया है।

इस हार के बाद आलाकमान ने हिमाचल प्रदेश पर ध्यान देना शुरू कर दिया और प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना से तमाम तरह की रिपोर्ट मंगवानी शुरू कर दीं। इस दौरान आरएसएस की प्रदेश इकाई और उत्तरी इकाई से भी रपट मंगवाई गई। संघ ने चंडीगढ़ में भी बैठकें कीं। राजधानी शिमला में कार्यसमिति की बैठकें हुई। शिमला में प्रदेश प्रभारी के साथ सौदान सिंह को भी भेजा गया।

इनकी रपट आलाकमान की ओर से देख लेने के बाद 15 दिनों के भीतर धर्मशाला में हुई बैठकों में प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना और सौदान सिंह के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष तक को जायज़ा लेने भेजा गया। धर्मशाला में भी तीन दिन तक मंथन करने के बाद जो रपट आलाकमान को गई है उन्हें पूरी तरह से गुप्त रखा गया है। लेकिन बाहर जिस तरह की जानकारियां मिल रही हैं उससे साफ है कि ये रपट बहुत ज़्यादा उत्साहजनक नहीं है। अब तमाम लोगों की ओर से आलाकमान को अपनी रपट दे चुकने के बाद आलाकमान के निर्देशों का इंतज़ार किया जा रहा है। इन तमाम नेताओं ने इन रपट में प्रदेश की तमाम ज़मीनी स्थिति का ख़ाका आलाकमान के पास रख छोड़ा है। लेकिन आलाकमान ने इन तमाम रपट को अपनी बगल में दबाकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को ज़मीनी स्थिति का खुद पत लगाने के लिए प्रदेश भेजा। नड्डा अपने दो दिवसीय दौरे पर हिमाचल आए और तमाम स्थितियों से रूबरू भी हुए और अपने अंदाज़ में वे नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी

बाक़ी पेज 11 पर

नए रूप में नज़र आएगी डब्ल्यूटीसी-2

भारत विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के दूसरे चक्र में भी पाकिस्तान से नहीं खेलेगा और उसे अगले दो सालों में तीन दौरे करने हैं जिसकी शुरुआत इंग्लैंड भारत से के साथ होगी। आइसीसी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि डब्ल्यूटीसी-2 के दौरान जीत दर्ज करने पर 12 अंक, ड्रॉ पर चार अंक और मैच टाई होने पर छह अंक दिए जाएंगे।

डब्ल्यूटीसी कैलेंडर में नौ देशों को अपनी पसंद के छह देशों के ख़िलाफ़ खेलना है और 2021-23 चक्र में भारतीय टीम वेस्टइंडीज के बजाय श्रीलंका से खेलेगी। भारतीय टीम चार अगस्त से इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज से डब्ल्यूटीसी अभियान की शुरूआत करेगी। टीम को दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 के बीच दक्षिण अफ्रीका का दौरा भी करना है, फिर उसे नवंबर 2022 में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ उसकी ही सरज़मी पर सीरीज खेलनी है।

इनके अलावा भारत इस वर्ष नवंबर में दो टेस्ट मैचों के लिए न्यूजीलैंड और फरवरी से मार्च 2022 तक श्रीलंका की मेज़बानी करेगा। आइसीसी ने आगे कहा कि जीते गए अंकों के प्रतिशत का उपयोग 2021-23 चक्र में स्थानों का निधारण करने के लिए किया जाएगा। इससे पहले प्रत्येक टेस्ट सीरीज के लिए 120 अंक तय किए गए थे जिससे असमानता पैदा होती थी।

जून 2023 में समाप्त होने वाले डब्ल्यूटीसी-2 में पांच टेस्ट की केवल दो सीरीज शामिल हैं। इनमें भारत-इंग्लैंड सीरीज के अलावा इस वर्ष आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाली एशेज सीरीज शामिल है। आस्ट्रेलिया के अगले वर्ष के भारत दौरे में चार टेस्ट मैच खेले जाएंगे। यह नए चक्र में चार मैचों की एकमात्र सीरीज होगी।

घरेलू सीरीज़

इंग्लैंड	(5)	वेस्टइंडीज	(2)	द. अफ्रीका	(3)
पाकिस्तान	(2)	श्रीलंका	(2)	भारत	(02)
भारत	(05)	न्यूजीलैंड	(3)	द. अफ्रीका	(3)
न्यूजीलैंड	(2)	श्रीलंका	(3)	आस्ट्रेलिया	(04)
बांग्लादेश	(2)	द. अफ्रीका	(02)	श्रीलंका	(02)
आस्ट्रेलिया	(02)	न्यूजीलैंड	(02)	इंग्लैंड	(03)
भारत	(03)	बांग्लादेश	(02)	वेस्टइंडीज	(02)
आस्ट्रेलिया	(02)	पाकिस्तान	(02)	वेस्टइंडीज	(02)
पाकिस्तान	(02)	इंग्लैंड	(03)	बांग्लादेश	(02)

डब्ल्यूटीसी-2

(2021-2023) के तहत होने वाली सीरीज़

टीमें	मैच
आस्ट्रेलिया	(18)
बांग्लादेश	(12)
इंग्लैंड	(22)
भारत	(19)
न्यूजीलैंड	(13)
पाकिस्तान	(13)
द. अफ्रीका	(15)
श्रीलंका	(13)
वेस्टइंडीज	(13)

विदेश में खेली जाने वाली सीरीज

पाकिस्तान	(2)	श्रीलंका	(2)	भारत	(04)
न्यूजीलैंड	(2)	द. अफ्रीका	(3)	वेस्टइंडीज	(02)
आस्ट्रेलिया	(05)	वेस्टइंडीज	(03)	पाकिस्तान	(03)
इंग्लैंड	(05)	द. अफ्रीका	(03)	बग्लादेश	(02)
भारत	(02)	इंग्लैंड	(03)	पाकिस्तान	(02)
वेस्टइंडीज	(02)	बांग्लादेश	(02)	श्रीलंका	(02)
न्यूजीलैंड	(02)	इंग्लेंड	(03)	आस्ट्रेलिया	(03)
बांग्लादेश	(02)	भारत	(03)	न्यूजीलैंड	(02)
दक्षिण अफ्रीका	(02)	श्रीलंका	(02)	आस्ट्रेलिया	(02)

लंबे समय तक नहीं खेलने से स्वयं पर संदेह होने लगता है : कुलदीप

भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव उन खिलाड़ियों से भिन्न है जो कुछ मैचों में ख़राब प्रदर्शन से स्वयं को चुका हुआ मानने लगते हैं हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि जब किसी खिलाड़ी को लंबे समय तक नज़रअंदाज़ किया जाता है तो वह ख़ुद पर संदेह करने लगता है।

कुलदीप का वनडे विश्वकप 2019 तक चयन तय माना जाता था लेकन अभी ऐसा नहीं है और उन्हें मुख्य टीम में जगह नहीं मिलती है। इस वर्ष के शुरू में इंग्लैंड के ख़िलाफ पुणे में खराब प्रदर्शन से उसके कैरियर को धक्का लगा था। उस मैच में उन्होंने 84 रन लुटाए थे और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था। कुलदीप ने श्रीलंका के ख़िलाफ़ पहले वनडे में 48 रन देकर दो विकेट लेकर अच्छी वापसी की। भारत ने यह मैच सात विकेट से जीता। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ उस मैच के बाद मुझे किसी भी समय ऐसा नहीं लगा कि सीमित ओवरों का मेरा कैरियर समाप्त हो गया है।

कई बार ऐसा होता है जब आप रन लुटाते हो। मैंने मैचों में चार और पांच विकेट भी लिए हें और यदि लोग उनके बारे में चर्चा करें तो बेहतर होगा। बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर ने कहा कि एक या दो ख़राब मैचों से किसी का कैरियर समाप्त नहीं हो जाता।

मुझे लगता है कि जिसने भी यह खेल खेला होगा या इस खेल की जानकारी रखता होगा वह इससे भी वाकिफ़ होगा। अब तक 64 वनडे में 107 विकेट लेने वाले कुलदीप ने पुणे (इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला) का विकेट बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छा था और उससे स्पिनरों को विशेष मदद नहीं मिल रही थी। जब विकेट आपके अनुकूल नहीं हो तो ऐसा हो सकता है।

कोविड-19 के समय में खिलाड़ियों को जैव सुरक्षित माहौल में रहना पड़ रहा है। कुलदीप इस बीच टीम में अंदर-बाहर होते रहे लेकिन उन्हें खेलने के अधिक मौके नहीं मिले जिसके गलत प्रभाव भी पड़े।

उन्होंने कहा कि जैव सुरक्षित वातावरण में जिंदगी काफी मुश्किल होती है और तब और परेशानी होती है जब आप खेल नहीं रहे हों क्योंकि आप स्वयं पर संदेह करने लगते हैं। लेकिन जब आप बहुत लोगों से बात करते हो तो नई तरह के संदेह पैदा होने लगते हैं।

बदलते मौसम में बच्चे का यूं रखें ख़्याल

मौसम बदल रहा हो तो अपने ख़्याल के साथ-साथ बच्चों का ख़्याल रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ज़रा सी लापरवाही आपके बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। इसलिए मानसून के मौसम में मां-बाप की ज़िम्मेदार बढ़ जाती है। आइये जानते हैं कि कुछ बातों का ध्यान रखकर हम कैसे अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं।

मानसून के मौसम में जगह-जगह पानी खड़ा होने और कीचड़ के कारण गंदगी रहती है जिसमें कई तरह के जर्म्स हो सकते हैं। इसी मौसम में मच्छरों के साथ-साथ कई तरह के कीड़े मकौड़े पैदा हो जाते हैं। ऐसे में घर और आस-पास की सफाई का विशेष ख़्याल रखें। घर के फर्श को धोने के लिए फिनाइल का इस्तेमाल करें क्योंकि बच्चे घर में अक्सर फर्श पर बैठ जाते हैं जिससे उन्हें इंफेक्शन का ख़तरा रहता है। बाहर से आने के तुरंत बाद उनके हाथ धुलाएं। बच्चों के सोने और बैठने वाली जगहों की साफ-सफाई का भी विशेष ध्यान रखें।

खिलाएं घर का खाना

बरसात के मौसम में कई तरह के बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। ऐसे में सही यही होगा कि बच्चों का बिल्कुल भी बाहर का खुला खाना कुछ न खिलाएं। उन्हें घर में बना खाना ही खिलाएं। ज़्यादा देर रखा हुआ खाना भी अवॉइड ही करें। हां, मौसमी फल ज़रूर दिए जा सकते हैं। इससे बच्चों में रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी।

भीगने से बचाएं

बारिश के मौसम में भीगना आम बात है। यदि ऐसा हो जाए तो बच्चों को तुरंत साफ पानी से नहलाएं और उसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहनने को दें। नहलाने के बाद उन्हें काढ़ा ज़रूर पिलाएं। कोशिश करें ऐसे मौसम में बच्चों को कॉटन के कपडे ही पहनाएं।

मानसून के मौसम में बच्चों में संक्रमित होने की संभावना अधिक होती है। वैसे भी पानी से इंफेक्शन होने का खतरा ज़्यादा रहता है। ऐसे में हो सके तो बच्चों को फिल्टर्ड या फिर उबला हुआ पानी ही पीने

बाक़ी पेज 11 पर

फ्रिज में न रखें ये फल

आज हम जिस कोरोना काल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसमें हर क्षेत्र में अतिरिक्त सावधानियाँ बरतनी पड़ रही हैं, वह चाहे खान पान से, बाहर जाने के मामले में हो, या फिर लोगों से मिलने इत्यादि हर क्षेत्र में हम पहले से बिल्कुल भिन्न व्यवहार और आचरण कर रहे हैं। इस काल में हमें खाने पीने की वस्तुएं के रख-रखाव पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है विशेषकर फल। आईये जानते हैं कुछ टिप्स फलों के बारे में। अधिकतर लोग फल, सब्ज़ियों और खाने के सामान को ख़राब होने से बचाने के लिए उन्हें फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कुछ ऐसे फल भी हैं जिन्हें फ्रिज में रखने से वे ख़राब हो जाते हैं। आईए जानते हैं ऐसे कुछ फलों के बारे में :-

लीची : ये गर्मी के सीजन का फल है। अधिकतर लोग बाजार से लीची लाकर उसे ख़राब होने से बचाने के लिए फ्रिज में रख देते हैं, जो कि ग़लत है। लीची फ्रिज में रखने से जल्दी ख़राब होने लगती है।

आम : फलों का राजा आम को खराब होने से बचाने के लिए महिलाएं उसे अक्सर फ्रिज में स्टोर करके रख देती हैं। ऐसा करने से आम और ख़राब हो जाते हैं, साथ ही उनकी महज फ्रिज में रखी अपने चीज़ों में भी आने लगती है।

केला : कले को भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। आप देखेंगे कि केला फ्रिज में रखने से उसमें काले धब्बे पड़ने लगते हैं और वह जल्दी ख़राब होने लगते है।

शेष.... इस विदाई पर कोई रोए या हँसे

कड़ी चुनौती पेश की थ। वे एक बार फिर ख़ाली हो रहे हैं और आईएसआई उन्हें उनके मनपसंद काम में लगाने के लिए शीघ्रातिशीघ्र कश्मीर रवाना करना चाहेगी। ग़नीमत यह है कि लड़ाकुओं का एक बड़ा तबक़ा, जो आईएसआई के असर में नहीं है, पाकिस्तानी में इस्लामी शरिया लागू करने के लिए जेहाद करना चाहेगा। शायद इसीलिए पाकिस्तानी तंत्र पिछले उत्साह की तरह तालिबानी फतह का स्वागत करने से गुरेज़ कर रहा है।

अमेरिकी फौज के लौटने के बाद विश्व को औरतों, शिया और हाशिए पर स्थित दूसरे वर्गों के मानवाधिकारों के वैसे ही उल्लंघनों के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसे उनके पहले शासनकाल में दिखे थे। शायद यही कारण है कि अमेरिका की उपस्थिति के धुर विरोधी भी यह समझ नहीं पा रहे हैं कि वे मनचाही मुराद पूरी होने के बाद ख़ुशी कैसे व्यक्त करें।❑❑

शेष.... औरंगजेब आलमगीर....

दी थी, सिंह बहादुर को दक्षिण में कलेक्टर बनाया गया था। इसी तरह राजा मानसिंह राव राय सिंह जसौदिया, दिलीप सिंह राजा इन्द्रमन, राजा संघहाड़ा, राव भाऊ सिंह हाड़ा, मोहकम सिंह, बैरम देव जोदयाराव गोपाल सिंह जहान सिंह, रूप सिंह दरबार आलमगीर के आला सिविल हुक्काम थे, राजा राज रूप को जम्मू कांगड़ा की इस्टेट अता की थी। राजा रतन सिंह मालवा के गवर्नर का मुशीर था राव अमर सिंह चन्द्र रावत को चित्तौड़ के करीब रामपुर की जागीर दी गयी थी, यह दक्षिण की जंग में जयसिंह के साथ था। लाला लाजपतराय ने अपनी किताब ''शिवाजी में लिखा है, कि दरअसल हिन्दुओं की जड़ काटने वाले हिन्दू ही थे। राजा जय सिंह, हरीभान उदयभान, कबीरत सिंह करण सिंह राठौर, शेर सिंह राठौर राजा जय सिंह हरीभान, कीरत सिंह, राज सिंह गौड़, उदरमल, चतुरभुज सिंह चौहान, मतर हुसैन जगत सिंह, राम सिंह हाड़ा वगैरहा वह फौजी जरनैल अहद आलमगीरी के थे जो शिवाजी के मुक़ाबले में औरंगज़ेब की तरह दिल खोलकर लड़ते थे, इन तफ्सीली वाक्यात से अब अवाम को खुद ही फैसला करना चाहिए ताकि तंगनज़र लोग जिन्हें अंग्रेज़ों से यह बदगुमानी विरसे में मिली थी किस मुंह से मुसलमान बादशाहों को ग़ैर मुस्लिमों का दुश्मन बताते हैं तारीख़ ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं कर सकती। यह अंग्रेज़ था जिसने हमारी गंगा जमनी तहज़ीब की बहादुरी को फिरक़ावारियत के रंग में रंग दिया ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक हुकूमत करने को मिलती है।❑❑

शेष.... बदलते मौसम में....

को दें। जर्म्स से बचने के लिए जर्म्स रिपेलेंट लिक्विड का इस्तेमाल किया जा सकता है।

मच्छरों को न पनपने दें

बारिश के साथ मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां फैलने लगती हैं। इनका प्रमुख कारण मच्छर है। इसलिए घर में और आस-पास मच्छरों को न पनपने दें। कूलर, गमलों और टब आदि में पानी इकट्ठा न होने दें। समय-समय पर साफ सफाई करते रहें। कोशिश करें बच्चों को मच्छरदानी में सुलाएं।

खान-पान में स्वच्छता रखें

बच्चे खान-पान में गंदगी से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। बच्चों को जो भी खाने के लिए दें, उसे साफ पानी से अच्छी तरह से धो लें। भोजन खिलाना हो तो गर्म-गर्म ही परोसें। परोसने से पहले अपने हाथ भी अच्छी तरह से धो लें। बच्चे को हर बार खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद साबुन से हाथ धोने की आदत डालें।❑❑

शेष.... मंज़र पस-मंज़र

यह हुआ कि लोगों के जीवन के आख़िरी दस वर्ष तरह- तरह की बीमारियों से जूझते हुए गुज़रते हैं। एक और दिलचस्प ट्रेंड यह देखा गया है कि विभिन्न देशों में औसत आयु तो बढ़ रही है, लेकिन स्वस्थ्य औसत आयु में वैसी बढ़ोत्तरी नहीं दिख रही। यानि महिला और पुरुषों के बीच का अंतर समस्या का सिर्फ एक पहलू है। बुज़ुर्ग आबादी के स्वास्थ्य का पहलू अलग से भी कम महत्वपूर्ण नहीं। अच्छी बात यह है कि दोनों में से कोई भी पहलू विशेषज्ञों की नज़रों से अछूता नहीं है। परिवार में पितृसत्तात्मक सोच के प्रभाव में महिलाओं के स्वास्थ्य को ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती। खाने-पीने के मामले में भी महिलाएं खुद को पीछे रखना उपयुक्त मानती हैं। इसके अलावा आर्थिक आत्मनिर्भरता के अभाव में स्वास्थ्य सेवाओं तक महिलाओं की सीधी पहुंच अमूमन नहीं हो पाती। जैसे-जैसे महिलाओं की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, इस मोर्चे पर सुधार की उम्मीद की जा सकती है लेकिन जहां तक वैश्विक स्तर पर औसत आयु और स्वस्थ औसत आयु में अंतर का प्रश्न है तो वहां मामला नीतियों और योजनाओं की दिशा का भी है। विभिन्न सरकारों का ही नहीं वैश्विक स्तर पर मेडिकल रिसर्चों के लिए होने वाली फंडिंग में भी जोर मौत के कारणों को समझने और दूर करने पर रहता है जिसका नकारात्मक नतीजा औसत आयु में बढ़ोत्तरी के रूप में नज़र आता है। अब ज़रूरत बुजुर्ग आबादी को होने वाली बीमारियों पर ध्या केन्द्रित करने की है ताकि उसे उन बीमारियों से बचाने के उपाय समय रहते किए जा सकें। तभी हम अपने बुज़ुर्गों के लिए लंबा और साथ ही अच्छी सेहत से युक्त जीवन सुनिश्चित कर पाएंगे।❑❑

स्विस बैंकों में भारतीयों का कोष बढ़कर रूपये 20,700 करोड़ हुआ

स्विस बैंकों में भारतीयों का व्यक्तिगत और कंपनियों का पैसा 2020 में बढ़कर 2.55 अरब स्विस फ्रेंक (20,700 करोड़ रुपये से अधिक) पर पहुंच गया। यह वृद्धि नक़द जमा के तौर पर नहीं बल्कि प्रतिभूतियों, बांड समेत अन्य वित्तीय उत्पादों के ज़रिये रखी गई होल्डिंग से हुई है। हालांकि, इस दौरान ग्राहकों की जमा राशि कम हुई है। स्विटजरलैंड के केन्द्रीय बैंक द्वारा जारी सालाना आंकड़े से यह जानकारी मिली। स्विस बैंकों में यह कोष भारत स्थित शाखाओं और अन्य वित्तीय संस्थानों के ज़रिये रखे गए हैं। स्विस बैंकों में भारतीय ग्राहकों का सकल कोष 2019 के अंत में 89.9 करोड़ स्विस फ्रेंक (6,625 करोड़ रुपये) था। यह 2020 में बढ़कर 2.55 अरब स्विस फ्रेंक पर पहुंच गया। इससे पहले, लगातार दो वर्ष इसमें गिरावट आई। ताज़ा आंकड़ा 13 वर्ष का सर्वाधिक है। स्विस नेशनल बैंक (एसएनबी) के आंकड़े के अनुसार 2006 में करीब 6.5 अरब स्विस फ्रेंक के रिकॉर्ड स्तर पर था। उसके बाद इसमें 2011, 2013 और 2017 को छोड़कर गिरावट आई। एसएनबी के अनुसार 2020 के अंत में भारतीय ग्राहकों के मामले में स्विस बैंकों की कुल देनदारी 255.47 करोड़ सीएचएफ (स्विस फ्रेंक) हैं इसमें 50.9 करोड़ स्विस फ्रेंक (4,000 करोड़ रुपये से अधिक) ग्राहक जमा के रूप में है। वहीं 38.3 करोड़ स्विस फ्रेंक (31,00 करोड़ रुपये से अधिक) अन्य बैंकों के ज़रिये रखे गए हैं। न्यास के ज़रिये 20 लाख स्विस फ्रेंक (16.5 करोड़ रुपये) जबकि सर्वाधिक 166.48 करोड़ स्विस फ्रेंक (करीब 13,500 करोड़ रुपये) बांड, प्रतिभूति और अन्य वित्तीय उत्पादों के रूप में रखे गए हैं। एसएनबी ने कहा कि ग्राहक खाता जमा के रूप में वर्गीकृत कोष वास्तव में 2019 की तुलना में कम हुआ है। वर्ष 2019 के अंत में यह 55 करोड़ स्विस फ्रेंक था। ट्रस्ट यानि न्यास के ज़रिये रखा गया धन भी 2019 में 74 लाख स्विस फ्रेंक के मुक़ाबले पिछले वर्ष आधे से भी कम हो गया हैं हालांकि दूसरे बैंकों के माध्यम से रखा गया कोष 2019 के 8.8 करोड़ स्विस फ्रेंक के मुक़ाबले तेज़ी से बढ़ा है। वर्ष 2019 में चारों मामलों में कोष में कमी आई थी। ये आंकड़े बैंकों ने एसएनबी को दिए हैं और यह भारतीयों द्वारा स्विटजरलैंड के बैंकों में रखे जाने वाले धन के बारे में कोई संकेत नहीं देता है। इन आंकड़ों में यह राशि भी शामिल नहीं है जो भारतीय, प्रवासी भारतीय या अन्य तीसरे देशों की इकाइयों के ज़रिये स्विस बैंकों में रख सकते हैं। एसएनबी के अनुसार उसका आंकड़ा भारतीय ग्राहकों के प्रति स्विस बैंकों की कुल देनदारी को बताता है।

शेष.... प्रथम पृष्ठ

वाली भाजपा ने समय के साथ कितनी शानदार यात्रा की है, इससे आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है।

महाराष्ट्र में पूर्व शिवसैनिक और आक्रामक नेता नारायण राणे को एमएसएमई मंत्री बनाकर मोदी ने शिवसेना को स्पष्ट संदेश दे दिया है। दिल्ली से डॉ. हर्षवर्धन गए तो मीनाक्षी लेखी आई और इसी तरह उत्तराखण्ड से ब्राह्मण रमेश पोखरियाल निशंक गए तो अजय भट्ट आए लेकिन सबसे शानदार तरीके से जाति और क्षेत्र का संतुलन बैठाने में मोदी को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली है। सपा/बसपा से आए आगरा के सांसद एसपीएस बघेल हों या फिर मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर। किशोर ने योगी सरकार के कोरोना प्रबंधन पर सवाल भी उठाए थे, लेकिन उन्हें मंत्री बनाया गया। बघेल और पासवान समाज के बड़े नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करके मोदी ने दो संदेश दिए हैं। पहला सामाजिक समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया, दूसरा - किसी भी पार्टी के ताक़तवर नेता के लिए भाजपा में सम्मानपूर्वक रहने का पूरा अवसर है। मोदी ने लखीमपुर खीरी से दो बार के भाजपा सांसद अजय कुमार मिश्र को मंत्री बनाकर इसका जवाब दे दिया कि क्या भाजपा के पास ब्राह्मण नेता नहीं है? अनुप्रिया पटेल को सहयोगी और पटेलों में संदेश देने के लिए मंत्री बनाया तो लगे हाथ महाराजगंज से लगातार सांसद बनने वाले कुर्मी नेता पंकज चौधरी को मंत्री बनाकर यह भी स्पष्ट किया कि भाजपा में किसी भी जाति के नेताओं की कमी नहीं है। सही मायने में पूरे देश में राजनीतिक संतुलन के साथ सुशासन के पैमाने पर नरेन्द्र मोदी की दूसरी अब शुरू हो गई है।

बहरहाल मोदी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जिसको जो काम सौंपा गया है, वह उस काम को किस स्तर तक ले जाता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा, फिलहाल तो इस मंत्रिमंडल विस्तार को 5 राज्यों में होने वाले चुनावों की रूपरेखा के तौर पर भी देखा जा रहा है।❑❑

शेष.... धामी के ज़रिए भाजपा साधेगा कुमाऊं

बहुगुणा को गढ़वाल के प्रतिनिधि के तौर पर कांग्रेस ने 2012 में मुख्यमंत्री बनाया था।

21 वर्ष पहले 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई थी तब किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि यह राज्य राजनीतिक उठापटक का सबसे बड़ा केन्द्र बन जाएगा। भाजपा ने पहला मुख्यमंत्री मैदानी मूल के नित्यानंद स्वामी को बनाया था और पर्वतीय मूल के नेताओं भगत सिंह कोश्यारी, भुवन चंद खंडूरी और रमेश पोखरियाल निशंक को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तब पर्वतीय मूल के लोगों ने एक मैदानी मूल के व्यक्ति को उत्तराखंड का पहला मुख्यमंत्री बनाने का ज़बरदस्त विरोध किया था जिस कारण 2002 के पहले विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता ने भाजपा को नकार दिया और राज्य में कांग्रेस की पहली निर्वाचित सरकार बनी। उसके बाद भाजपा ने किसी मैदानी मूल के नेता को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाने की भूल नहीं की। भाजपा ने पहली बार मैदानी मूल के सदन कौशिक को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जबकि कांग्रेस ने कभी भी मैदानी मूल के राजनेता को सरकार और पार्टी की कमान नहीं सौंपी।

वैसे तो भाजपा में उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री को बनाने की पटकथा 10वें मुख्यमंत्री के रूप में तीरथ सिंह रावत के शपथ लेने के साथ ही 10 मार्च को ही लिख दी गई थी। मुख्यमंत्री बनने के दो दिन बाद ही तीरथ सिंह रावत अपने विवादित बयानों के कारण चर्चित हो गए। भाजपा आलाकमान ने उन्हें कभी भी गंभीर मुख्यमंत्री के रूप में नहीं लिया। लिहाज़ा उन्हें विधान सभा के चुनाव लड़ाने के लिए किसी भी विधायक को सीट ख़ाली करने के लिए निर्देश नहीं दिए।❑❑

शेष.... पार्टी की तमाम रपट में तो....

मिले। सूत्रों के मुताबिक नड्डा के प्रदेश दौरे से पहले राजधानी से नेताओं की एक जोड़ी दिल्ली का गुप्त दौरा कर आई है।

ग़ौर रहे कि हिमाचल प्रदेश नड्डा का गृह प्रदेश है और वह यहां की राजनीति से पूरी तरह से वाक़िफ ही नहीं यहां की राजनीति का हिस्सा भी है। यह दीगर है कि जब 15 जून से 30 जून तक शिमला से लेकर धर्मशाला तक चले भाजपा के मंथन शिविर से उन्होंने खुद को अलग रखा। मुख्यमंत्री जयराम ने स्थितियों को भांपते हुए अपना पूरा कुनबा नड्डा की आवभगत में झोंक दिया। नड्डा के हेलीकॉप्टर से उतरने से लेकर तमाम समय तक सरकार व संगठन उनकी आवभगत में लगा रहा। ज़ाहिर है जयराम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। वे जानते हैं कि उत्तराखंड में क्या हुआ है और नड्डा ने कैसे चार माह में वहां के दो मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा मांग लिया है। चूंकि प्रदेश में तीन उपचुनाव होने हैं, ऐसे में आलाकमान हिमाचल को लेकर काफी सक्रिय है। बड़ा प्रश्न यही है कि क्या जयराम जीत का सिलसिला जारी रख पाएंगे।

बहरहाल, भीतरी सूत्रों के मुताबिक आरएसएस में राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न जगहों पर हिमाचल से दर्जनों पदाधिकारी तैनात हैं जिनकी जयराम के अलावा अन्य किसी नेता पर मुख्यमंत्री को लेकर सहमति नहीं बन रही है इसलिए संघ के ये पदाधिकारी प्रदेश में किसी तरह के बदलाव के पक्ष में नहीं है। लेकिन जब तक आलाकमान की ओर से नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर खुल कर विराम नहीं दे दिया जाता तब तक जयराम की कुर्सी को लेकर अटकल जारी रहेंगी जो प्रदेश भाजपा के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होने वाली है।❑❑

SHANTI MISSION (HINDI WEEKLY) NEW DELHI Postal Registration No. DL(C)-01/1266/2021-23
Publishing Date : **18 July2021** Posting Days : **MON. - TUE.** at **N.D.P.S.O.** New Delhi-110002 R.N.I. 57270/93

मंज़र पस-मंज़र — मीम.सीन.जीम

•बुनियदी चुनौती•भूख से मौतें •जीवन लम्बा हो स्वस्थ्य भी

बुनियादी चुनौती

कुपोषण और भुखमरी पर वैश्विक रिपोर्टें चौंकाने वाली ही होती है इनसे यही पता चलता है कि दुनियाभर में कुपोषितों का आंकड़ा कितना और बढ़ा। लेकिन ज़्यादा चिंताजनक यह है कि तमाम कोशिशों और दावों के बावजूद कुपोषितों और भुखमरी का सामना करने वालों का आंकड़ा पिछली बार के मुक़ाबले बढ़ा हुआ ही निकलता है। ऐसी रिपोर्टें बताती हैं कि ऐसी गंभीर समस्याओं से लड़ते हुए हम कहां पहुंचे। इसी में एक बड़ा प्रश्न यह भी निकलता है कि जिन लक्ष्यों को लेकर दुनिया के देश सामूहिक तौर पर या अपने प्रयासों के दावे करते रहे हैं, उनमें कामयाबी कितनी मिली। कुपोषण, ग़रीबी और भुखमरी में सीधा रिश्ता है। यह दो-चार देशों ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत बड़े भूभाग के लिए चुनौती बनी हुई है। दुनिया से लगभग आधी आबादी इन समस्याओं से जूझ रही है। इसीलिए यह प्रश्न तो उठता ही रहेगा कि इन समस्याओं से जूझने वाले देश आख़िर क्यों नहीं इनसे निपट पा रहे हैं। हाल में एक अध्ययन में यह पता चला है कि दुनिया के तीन अरब लोग पौष्टिक भोजन से वंचित है। वास्तविक आंकड़ा इससे भी बड़ा हो तो हैरानी की बात नहीं। पर इतना ज़रूर है कि इतनी आबादी तो उस पौष्टिक खाद्य से दूर ही है जो एक मनुष्य को दुरुस्त रहने के लिए चाहिए। इनमें ज़्यादातर लोग गरीब और विकासशील देशों के ही हैं। ग़रीब मुल्कों में भी अफ़्रीकी, लैटिन अमेरिकी और एशियाई क्षेत्र के देश ज़्यादा हैं। गरीबी की मार से लोग अपने खानपान की बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाते। अगर शहरों में ही देख लें तो ग़रीब आबादी के लिए रोज़ाना दूध और आटा खरीदना भी भारी पड़ता है। राजनीतिक संघर्षों और गृहयुद्ध जैसे संकटों से जूझ रहे अफ़्रीकी देशों से आने वाली तस्वीरें तो और डरावनी है। खाने के एक-एक पैकेट के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती है। ऐसे में पौष्टिक भोजन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। महंगाई के कारण मध्य और निम्न वर्ग के लोग अपने खानपान के खर्च में भारी कटौती के लिए मजबूर होते हैं ऐसे में एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए निर्धारित मानकों वाले खाद्य पदार्थ उनकी पहुंच से दूर हो जाते हैं। पौष्टिक भोजन के अभाव में लोग गंभीर बीमारियों की ज़द में आने लगते हैं। ग्रामीण इलाकों में यह हाल और बुरा है। यह स्थिति किसी एक देश विशेष की नहीं, बल्कि सारे ग़रीब और विकासशील देशों में कमोबेश एक जैसी ही है। विकासशील देशों में भी कुछेक शहरों में अगर उच्च मध्य वर्ग तक के तबक़े को छोड़ दें तो बाक़ी आबादी का हाल ग़रीब मुल्कों में ज़िन्दगी काट रहे लोगों से बेहतर नहीं है।

खाने के एक-एक पैकेट के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती है। ऐसे में पौष्टिक भोजन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। महंगाई के कारण मध्य और निम्न वर्ग के लोग अपने खानपान के खर्च में भारी कटौती के लिए मजबूर होते हैं ऐसे में एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए निर्धारित मानकों वाले खाद्य पदार्थ उनकी पहुंच से दूर हो जाते हैं।

महामारी के डेढ़ वर्ष में कुपोषण के मोर्चे पर हालात और दयनीय हुए हैं। अब इस संकट से निपटने की चुनौती और बड़ी हो गई है। इसके लिए देशों को अपने स्तर पर तो जुटना ही होगा, वैश्विक प्रयासों की भूमिका भी अहम होगी। ग़रीब मुल्कों की मदद के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम को तेज़ करने की ज़रूरत है। विकासशील देशों को ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो ग़रीबी दूर कर सकें। उन देशों की सरकारों को अपना खाद्य तंत्र मजबूत बनाना होगा। पोषक तत्व वाले फल सब्ज़ी और प्रोटीन से भरपूर खाद्य उत्पाद उगाने के लिए किसानों को प्रेरित करना होगा। हालांकि इसके लिए भारी निवेश चाहिए। पर यह कोई असंभव काम नहीं है। सरकारें ठान लें तो हर नागरिक को पौष्टिक भोजन देना मुश्किल भी नहीं है।

भूख से मौतें

21वीं सदी में भी अगर यह सुनने को मिले कि भूख से हर मिनट में 11 लोगों की मौत हो रही है तो इससे ज़्यादा पीड़ादायक और क्या होगा। ऑक्सफेम ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में बताया है कि महामारी के दौर में भूख से दम तोड़ने वालों की तादाद सामान्य दिनों के मुक़ाबले काफी बड़ गई है। यह ज़्यादा चिंता की बात इसलिए भी है कि भुखमरी का सामना करने वालों की तादाद में दो करोड़ से ज़्यादा का इज़ाफ़ा हो गया हैं हो सकता है कि यह आंकड़ा और ज़्यादा भी हो। मोटा अनुमान बताता है कि पन्द्रह करोड़ से ज़्यादा लोगों भूखे पेट सो रहे हैं, या कई कई दिन बिना खाए गुज़ार रहे है। यह हालत अफ़्रीकी महाद्वीप के देशों से लेकर दुनिया के कई विकासशील देशों की है। पिछले एक वर्ष में हालात इसलिए भी ज़्यादा बिगड़े क्योंकि दुनिया के लगभग सारे देश महामारी और इसके दुष्प्रभावों का सामना कर रहे हैं। ज़ाहिर है ऐसे में सबसे ज़्यादा असर उन देशों पर ही पड़ रहा है जो हर तरह से ग़रीबी की मार झेलने को अभिशप्त हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटारेस ने तो वर्षभर पहले ही अंदेशा जता दिया था कि महामारी की मार से पांच करोड़ लोग और बेहद गरीबी में चले जाएंगे। उनका यह अंदेशा आज हक़ीक़त के रूप में सामने है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि आधी कि ज़्यादा अधिक गरीबी और भुखमरी की समस्या से जूझ रही है। हालांकि महामारी से पहले भी स्थिति कम विकट नहीं थी। पर महामारी ने इसे और बदतर कर डाला। भुखमरी की समस्या उन देशों में कहीं ज़्यादा विकराल है जो गृहयुद्ध जैसे संकट से जूझ रहे हैं, राजनीतिक और सामाजिक संघर्षों का सामना कर रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र व अन्य विदेशी मदद पर निर्भर हैं। पिछले एक वर्ष में ज़्यादा मुश्किल इसलिए भी खड़ी हुई क्योंकि वैश्विक खाद्य कार्यक्रम को मदद देने वाले देश ही महामारी के संकट में फंस गए। गौरतलब है कि वैश्विक खाद्य कार्यक्रम और दूसरे राहत अभियानों के लिए अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी, फ्रांस जैसे धनी देश मदद देते रहे हैं। लेकिन अब इन देशों की अर्थव्यवस्था भी चरमराई पड़ी है। पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने करीब बीस करोड़ लोगों को राहत पहुंचाने के लिए पैंतीस अरब डॉलर की मांग की थी। पर मिले सिर्फ सत्रह अरब डॉलर ही थे। ऐसे में भुखमरी की समस्या से निपटने के लिए और मदद कौन देगा, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।

भुखमरी, गरीबी जैसी समस्याओं से निपटना चुनौतीभरा तो ज़रूर है, पर असंभव नहीं। आज जिन देशों में भी बड़ी आबादी इन गंभीर मानवीय संकटों का सामना कर रही है तो इसके मूल में उन देशों की नीतियां ही ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं। ज़्यादातर अफ़्रीकी और लैटिन अमेरिकी देश सत्ता संघर्ष जैसे संकट का सामना कर रहे हैं। गृहयुद्ध के कारण लोग देश छोड़ने को मजबूर हैं। विकासशील देशों में स्थिति इसलिए ख़राब है कि गरीब तबक़े को लेकर सरकारों का रुख़ और नीतियाँ उपेक्षापूर्ण ही रहती आई हैं इसलिए भुखमरी और ग़रीबी से निपटने की योजनाएं बनती भी हैं तो वे सिरे नहीं चढ़ पातीं और आबादी का बड़ा हिस्सा ग़रीब ही बना रहता है। ग़रीबी, कुपोषण और भुखमरी जैसे समस्याएं ही राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ी बाधा साबित होती हैं। ऐसे में ग़रीब तबक़े के उत्थान के प्रति सरकारों की ज़िम्मेदारी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सरकारें जागरुक और जनसरोकार वाली हों तो उस देश में कम से कम भूख से कोई नहीं मरेगा।

जीवन लंबा हो, स्वस्थ भी

हाल ही में आई वर्ल्ड हेल्थ स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट 2021 ने महिलाओं और पुरुषों की औसत आयु और उनके स्वास्थ्य से जुड़े कुछ पहलुओं पर नए सिरे से विचार की ज़रूरत बताई है। रिपोर्ट के मुताबिक़ दुनियाभर में महिलाओं की औसत आयु पुरुषों के मुक़ाबले अधिक है। वे अपेक्षाकृत ज़्यादा लंबा जीवन जीती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि स्वास्थ्य के मामले में भी वे पुरुषों से बेहतर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात औसत स्वस्थ आयु की हो तो महिलाओं और पुरुषों के बीच का यह अंतर काफी कम हो जाता है। स्वस्थ औसत आयु के लिहाज़ से महिलाएं और पुरुष करीब-करीब एक जैसी ही स्थिति में है। यानि जीवन के आख़िरी हिस्से में पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों का स्वास्थ्य ज़्यादा कमज़ोर होता है। अपने देश में भी औसत आयु के मामले में पुरुषों से तीन वर्ष आगे दिखतीं महिलाएं स्वस्थ औसत आयु का प्रश्न उठने पर पुरुषों के समकक्ष नज़र आने लगती हैं। अगर जेंडर के प्रश्न को छोड़कर इस मसले को संपूर्णता से देखा जाए तो बात थोड़ी और साफ होती है। वैश्विक औसत आयु 73.3 वर्ष है तो स्वस्थ्य औसत आयु 63.7 वर्ष। यानि दोनों के बीच करीब नौ वर्ष का अंतर है। इसका साफ मतलब

जीवन के आख़िरी हिस्से में पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों का स्वास्थ्य ज़्यादा कमज़ोर होता है। अपने देश में भी औसत आयु के मामले में पुरुषों से तीन वर्ष आगे दिखतीं महिलाएं स्वस्थ औसत आयु का प्रश्न उठने पर पुरुषों के समकक्ष नज़र आने लगती हैं। अगर जेंडर के प्रश्न को छोड़कर इस मसले को संपूर्णता से देखा जाए तो बात थोड़ी और साफ होती है।

बाक़ी पेज 11 पर

ज़रूरी ऐलान

आपकी ख़रीदारी अवधि पते की चिट पर अंकित है। अवधि की समाप्ति से पूर्व रक़म भेजने की कृपा करें।

रक़म भेजने के तरीक़े:-

❶ मनीआर्डर द्वारा ❷ **Paytm** या **PhonePe** द्वारा **9811198820** पर **SHANTI MISSION**

❸ ऑनलाइन हेतु बैंक खाते का विवरण
SBI A/c **10310541455**
Branch: **Indraprastha Estate**
IFS Code: **SBIN0001187**

ख़रीदारी चन्दा

वार्षिक	Rs.130/-
6 महीने के लिए	Rs.70/-
एक प्रति	Rs.3/-

जानकारी के लिये सम्पर्क करें
साप्ताहिक
शांति मिशन
1, बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग,
नई दिल्ली-110002
फोन : 011-23311455

अपने प्रिय अख़बार साप्ताहिक शांति मिशन को इंटरनेट पर देखने के लिये लॉगऑन करें:
www.aljamiat.in ——— www.jahazimedia.com
Mob. 9811198820 — E-mail: Shantimissionweekly@gmail.com

जमीअत ट्रस्ट सोसायटी की तरफ से मुद्रक, प्रकाशक शकील अहमद सैयद ने शेरवानी आर्ट प्रिंटर्स, 1480, क़ासिमजान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से छपवाकर मदनी हाल, न. 1, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित किया। संपादक:- मोहम्मद सालिम, फोन:- 23311455, 23317729, फैक्स:- 23316173